कमल संदेश
ikf{kd if=dk

संपादक

प्रभात झा, सांसद

कार्यकारी संपादक

डॉ. शिव शक्ति बक्सी

सहायक संपादक

संजीव कुमार सिन्हा

संपादक मंडल सदस्य

सत्यपाल

कला संपादक

विकास सैनी

सदस्यता शुल्क

वार्षिक : 100/-
त्रि वार्षिक : 250/-

संपर्क

InL;rk : +91(11) 23005798
Qku (dk-) : +91(11) 23381428
QDI : +91(11) 23387887
पता : डॉ. मुकर्जी स्मृति न्यास, पी.पी–66, सुब्रमण्यम भारती मार्ग, नई दिल्ली–110003

ई–मेल

kamalsandesh@yahoo.co.in

प्रकाशक एवं मुद्रक : डॉ. नन्दकिशोर गर्ग द्वारा डॉ. मुकर्जी स्मृति न्यास, के लिए एक्सेलप्रिंट, सी–36, एफ.एफ. कॉम्पलेक्स, झण्डेवालान, नई दिल्ली–55 से मुद्रित करा के, डॉ. मुकर्जी स्मृति न्यास, पी.पी–66, सुब्रमण्यम भारती मार्ग, नई दिल्ली–110003 से प्रकाशित किया गया। सम्पादक – प्रभात झा

विषय-सूची

संगठनात्मक गतिविधियां

बिहार चुनाव पर साझा प्रेस.......... 7
'पंच क्रांति अभियान' का शुभारम्भ.......... 8
पोर्ट ब्लेयर नगर निगम चुनावों में भाजपा की जीत.......... 9

सरकार की उपलब्धियां

भारत में कारोबार के लिए गुजरात सबसे सुगम राज्य : विश्व बैंक.......... 10
निशक्तजनों के लिए 'स्वावलंबन स्वास्थ्य बीमा योजना'.......... 11
स्मार्ट सिटी की तरह अब स्मार्ट बनेंगे गांव.......... 12

वैचारिकी :

पं. दीनदयाल उपाध्याय : व्यक्ति और विचार
डॉ. मुरली मनोहर जोशी.......... 13

श्रद्धांजलि

'लाल, अब मैं नहीं लिख पाऊंगा'
लाल कृष्ण आडवाणी.......... 17

लेख

बेटी जन्मे भी और पढ़े भी
- डॉ. सुधा मलैया.......... 18

साक्षात्कार

डॉ. अनिल जैन, भाजपा राष्ट्रीय महामंत्री.......... 20

अन्य

प्रधानमंत्री की चंडीगढ़, सहारनपुर तथा ऋषिकेश रैली.......... 22
प्रधानमंत्री का वाराणसी प्रवास.......... 23
दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव.......... 25
'मन की बात'.......... 26
इंडिया टीवी का बिहार चुनाव मंच कार्यक्रम.......... 27

कमल संदेश के सभी सुधी पाठकों को **नवरात्र** की हार्दिक शुभकामनाएं!

बोध कथा

समर्थ गुरु ने समझाया जीवन का वास्तविक प्रयोजन

छत्रपति शिवाजी अपने कौशल के जरिए दिल्ली के बादशाह के चंगुल से छूटकर लौटे थे। रास्ते में उन्होंने अपना जीवन दांव पर लगाते हुए एक गांव को दस्युओं के हाथों लुटने से भी बचाया था। लौटकर आने के बाद उनका यह पहला दरबार था। सिंहासन के दायीं ओर अष्ट प्रधानों के ऊंचे और भव्य आसन थे। बायीं ओर सामंतों की पंक्ति थी। सभी सभासद अपना-अपना स्थान ग्रहण किए हुए थे।

शिवाजी के लौटकर आने के बाद कोई गंभीर समस्या नहीं आई थी। शत्रु का समाचार न था और नवीन आक्रमण की भी कोई योजना अभी नहीं थी। यों इन सबके होने पर भी शिवाजी की निष्काम कर्म-वृत्ति उनके मानस पटल पर चिंता की लकीरें नहीं खिंचने देती थी। सभासदों के बीच चर्चा चल रही थी। तभी तानाबा ने एक प्रश्न पूछा – 'आखिर जीवन का वास्तविक प्रयोजन क्या है?'

शिवाजी इस प्रश्न का उत्तर देने ही वाले थे, तभी उन्हें द्वार पर समर्थ गुरु रामदास के आने की सूचना मिली। छत्रपति तुरंत द्वार की ओर दौड़ पड़े। सभासद भी उनके पीछे हो लिए। शिवाजी ने द्वार पर पहुंच गुरु को प्रणाम किया, उन्हें सम्मानपूर्वक भीतर लेकर आए और अपने राजसिंहासन पर बिठाया। इसके बाद शिवाजी ने समर्थ गुरु से कहा – 'प्रभु, तानाबा जानना चाहते हैं कि जीवन का असली मतलब क्या है? अब आप ही इस प्रश्न का समाधान करें।'

समर्थ गुरु ने शांत स्वर में जवाब दिया – 'गति और शक्ति! इन दोनों का संयुक्त ही जीवन है और उसका मतलब है सतत जागरूकता।' दरबार में सभी के नेत्र अब भी समर्थ गुरु के मुख पर इस तरह लगे थे कि वे अभी तृप्त नहीं हुए हैं। मूक नेत्र भाषा में सबने कुछ और सुनने की प्रार्थना की।

समर्थ गुरु उन सबका मंतव्य समझ गए और बोले – 'जिज्ञासा, प्रयत्न, विचार और त्याग का अविरल प्रवाह ही जीवन है। इनमें से किसी के भी मूर्छित होने का मतलब है जीवन की रुग्णावस्था। इनकी निवृत्ति में मृत्यु है और पूर्णता में मोक्ष। तुम सबको मोक्ष की ओर बढ़ना है। इनकी पूर्णता की परिणति है आनंद। इस आनंद की अभीप्सा ही यथार्थ जीवन है।'

(नई दुनिया से साभार)

पाथेय

राष्ट्रीयता का आधार – भारतमाता

हमारी राष्ट्रीयता का आधार 'भारत माता' है, केवल भारत नहीं? माता शब्द हटा दीजिए तो भारत केवल जमीन का एक टुकड़ा मात्र रह जाएगा। इस भूमि का और हमारा ममत्व तब आता है, जब माता वाला संबंध जुड़ता है। कोई भी भूमि तब तक देश नहीं कहला सकती, जब तक कि उसमें किसी जाति का मातृक ममत्व, याने ऐसा ममत्व जैसा पुत्र का माता के प्रति होता है, न हो। यही देशभक्ति है।

– पं. दीनदयाल उपाध्याय

सम्पादकीय

भाजपानीत राजग के नेतृत्व में बिहार अपना गौरव पुनः प्राप्त करेगा

बिहार में चुनावी बिगुल बज चुका है। जैसे ही चुनाव आयोग ने चुनाव की घोषणा की, प्रदेश में राजनैतिक गतिविधियां तेज हो गई और सभी राजनैतिक दल चुनावी तैयारियों में जुट गये। बिहार इस बार एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण चुनाव देखने जा रहा है जिसमें भाजपानीत एनडीए बहुत ही ताकतवर विकल्प के रूप में उभरा है। बिहार ने हमेशा से देश को महत्वपूर्ण राजनैतिक संदेश दिया है। पूरे देश के राजनैतिक पंडित बेसब्री से देख रहे हैं कि बिहार किस तरह से वोट करता है। बिहार ने हमेशा अवसरवादी राजनीति को खारिज किया है और जंगल राज के विरूद्ध जबरदस्त लड़ाई लड़ी है। राजद, जदयू एवं कांग्रेस का गठबंधन न केवल अवसरवादी है, बल्कि जंगलराज की वापसी की गारंटी भी है। देश की राजनीति जाति-पंथ के विभाजनकारी दौर से आगे बढ़ चुकी है। लोग सुशासन एवं विकास चाहते हैं। भाजपानीत राजग लोगों की एकमात्र आशा बनकर उभरी है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी राष्ट्र को विकास एवं गौरव की ओर ले जा रहे हैं। जैसा कि लोकसभा चुनावों से स्पष्ट है, लोगों ने विकास एवं सुशासन के पक्ष में अपना मन बना लिया है तथा अवसरवादी एवं जंगल राज की प्रतिगामी राजनीति को पाठ पढ़ाने को तैयार हैं।

लोकसभा चुनावों में बिहार ने भाजपा एवं नरेन्द्र मोदी को जबरदस्त समर्थन प्राप्त हुआ। भाजपा अपने सहयोगी दलों लोजपा एवं रालोसपा के साथ चुनावों में गई थी। जनता द्वारा राजग को उत्साहपूर्ण समर्थन प्राप्त हुआ तथा एनडीए को 40 में से 31 सीटें प्राप्त हुई। यह भाजपानीत एनडीए की भारी जीत थी। लोगों ने जाति-संप्रदाय से ऊपर उठकर नरेन्द्र मोदी को वोट दिया और एक बड़े परिवर्तन का मार्ग प्रशस्त किया। यह वोट सुशासन एवं विकास के लिए था। कांग्रेस और राजद के विभाजनकारी एवं प्रतिगामी राजनीति को लोग देख चुके थे और विकल्प तलाश रहे थे। राष्ट्रीय स्तर पर नरेन्द्र मोदी एक विकल्प के रूप में उभर चुके थे। 'सबका साथ, सबका विकास' का मंत्र पूरे देश में गूंज रहा था। लालू-कांग्रेस युग में बिहार विकास की दौड़ में पिछड़ चुका था। लोग इस स्थिति से बाहर निकलना चाहते थे। बिहार ने पूरे देश के स्वर में स्वर मिला दिया और परिवर्तन एवं विकास पर अपनी मुहर लगा दी। इसने नरेन्द्र मोदी और भाजपानीत एनडीए को चुना। लोकसभा चुनावों में एनडीए की जीत में बिहार ने बड़ा योगदान दिया।

लोकसभा चुनावों में बुरी तरह पराजित होने के बाद नीतीश कुमार ने बिहार की राजनीति को अवसरवादी मोड़ दिया। लोकसभा चुनावों में जदयू मात्र दो सीट जीत पाई थी। आने वाली विधानसभा चुनाव में अपने होने वाले हश्र को नीतीश कुमार साफ देख रहे थे। सत्ता से चिपके रहने की चाहत में नीतीश ने वह कर दिया जो किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था- वे लालू यादव से हाथ मिला बैठे। सुशासन बाबू का जंगलराज से गठबंधन हो गया। यही नीतीश कुमार लालू यादव के जंगलराज के खिलाफ जनता से समर्थन ले मुख्यमंत्री की गद्‌दी पर बैठे थे। और जब यह भारी अवसरवादी गठबंधन हुआ नीतीश कुमार ने दूसरे ड्रामे की शुरुआत की। मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे महादलित नेता जीतनराम मांझी को मुख्यमंत्री बना दिया। नीतीश कुमार ने सोचा था कि जीतन राम मांझी उनका रबर स्टाम्प मुख्यमंत्री होंगे। लेकिन जब उन्होंने उनके हाथ की कठपुतली बनने से इंकार कर दिया तब नीतीश कुमार के लिए उन्हें बर्दाश्त करना मुश्किल हो गया। नतीजा यह हुआ कि जीतन राम

मांझी को मुख्यमंत्री पद से हटना पड़ा। अब नीतीश और लालू दोनों का चेहरा जनता के सामने उजागर हो चुका है।

क्या नीतीश-लालू का गठजोड़ जनता का विश्वास प्राप्त कर सकता है? लालू के जंगल राज को कौन भूल सकता है- लालू-राबड़ी के वो 15 साल जब लोग बिहार से पलायन को मजबूर हुये, उद्योग-धंधे चौपट हो गये, मजदूरों को काम मिलना मुश्किल हो गया और किसान भगवान भरोसे जीने पर मजबूर थे। पूरा बिहार पिछड़ेपन एवं नकारात्मकता के गर्त में डूब गया था और लोग आतंक के साये में जी रहे थे। हत्या, लूट, अगवा, फिरौती, वसूली ये सब आम बात हो गई थी। बिहार की जनता ने एक लंबे संघर्ष के बाद एनडीए (तब जदयू एवं भाजपा) को जीत कर भाजपा के समर्थन से नीतीश को मुख्यमंत्री बनाया था। लेकिन नीतीश कुमार जिन्हें बिहार के विकास पर ध्यान केन्द्रित करना चाहिए था विभिन्न प्रकार के महत्वाकांक्षाओं को पालने लगे। अनेक ऐसे अवसर आये जब उन्होंने ऐसी परिस्थितियां बनाई जिसमें भाजपा को अपमान का घूंट पीना पड़ा। और जब उन्होंने देखा कि भाजपा की लोकप्रियता बढ़ रही है और नरेन्द्र मोदी देश के सबसे स्वीकार्य एवं लोकप्रिय नेता बन चुके हैं तो उन्होंने भाजपा के राह में रोड़ा अटकाने का प्रयास किया। जदयू एनडीए से बाहर हो गया। लेकिन बिहार की जनता ने अपना फैसला सुना दिया। लोकसभा चुनावों में जहां भाजपानीत एनडीए को भारी जनसमर्थन मिला वहीं जदयू-राजद को मुंह की खानी पड़ी।

बिहार विधानसभा चुनावों के परिणाम लोकसभा चुनावों से अलग नहीं होंगे। लालू यादव के राजद से गठबंधन नीतीश कुमार को अब और भी महंगा पड़ेगा। अवसरवादी गठबंधन से सत्ता में वापसी का सपना, अब सपना ही रहेगा। पहले तो इन्होंने 'जनता परिवार' को इकट्ठा कर एक बड़ी पार्टी बनाने का दावा किया। जब यह योजना सफल नहीं हुई तब कहा कि 'महागठबंधन' होगा। लेकिन जब यह भी नहीं हुआ तब लालू-नीतीश और कांग्रेस साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस के पास बिहार में कुछ भी पाने की स्थिति नहीं है, जो कुछ भी बचा है उसको समेटने में भी अब परेशानी महसूस कर रही है। राजद और जदयू तो पिछले लोकसभा चुनावों को घाव को ही सहला रही है, उससे उबर नहीं पाई है। क्या तीन शून्य मिलकर शून्य से कभी अधिक हो सकते हैं? क्या इन तीनों पार्टियों से जनता की कोई आशा अब बची हुई है? बिहार ने हमेशा अवसरवादी एवं सिद्धांतहीन राजनीति को सबक सिखाया है। बिहार का संदेश हमेशा लोकतंत्र एवं विकास का रहा है। जहां इसने कांग्रेस की ताकत को इसके कुशासन एवं भ्रष्टाचार के लिए पराजित किया वहीं लालू को जंगलराज के लिए भी दण्ड दिया है। भाजपा को धोखा देने एवं अवसरवादी पैंतरों के लिए लोकसभा चुनावों में बिहार ने नीतीश को भी पाठ पढ़ाया है। इस बार ये तीनों इकट्ठे हो गये हैं और जनता इनको धूल चटाने को आतुर है। एक ओर जहां भाजपानीत एनडीए सरकार बनाने जा रही है, इसमें अब कोई संदेह नहीं की दूसरी ओर बिहार नीतीश-लालू-कांग्रेस को भी पाठ पढ़ायेगी।

भाजपा अपने एनडीए के साथी लोजपा, रालोसपा एवं हम के साथ चुनाव मैदान में कूद चुकी है और अपने बीच सीटों के बंटवारे की भी घोषणा कर चुकी है। लोग एनडीए पर अपना विश्वास प्रकट कर रहे हैं और नरेन्द्र मोदी की जनसभाओं में व्यापक जनसमर्थन दिखाई पड़ रहा है। प्रधानमंत्री ने बिहार के लिए पूर्व में ही एक बड़े पैकेज की घोषणा की है और प्रदेश अब विकास के मार्ग पर बढ़ने के लिए तैयार है। एक और जहां केंद्र सरकार बिहार के विकास को रफ्तार दे रही है वहीं दूसरी ओर आवश्यकता यह है कि प्रदेश सरकार भी केन्द्र के कदम से कदम मिलाये नहीं तो परिणाम अनुकूल नहीं निकलेगा। इस संदर्भ में यह चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे बिहार का भविष्य तय होगा। बिहार की जनता इस बात को अच्छी तरह समझती है और अब निश्चय कर चुकी है की विकास के तेज रफ्तार से खोये हुए वर्षो को वापस पायेंगे। बिहार को आज एक प्रतिबद्ध नेतृत्व एवं समर्पित पार्टी की आवश्यकता है। भाजपानीत एनडीए बिहार को अवसरवाद एवं पिछड़ापन से बिहार निकालने को कृतसंकल्प है। भाजपानीत एनडीए के नेतृत्व में बिहार पुनः अपने गौरव को प्राप्त करेगा। ■

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी राजग के सर्वमान्य नेता हैं : अमित शाह

भाजपा मुख्यालय में 14 सितंबर को आयोजित बिहार राजग की साझा प्रेस वार्ता को भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह ने सम्बोधित किया और आगामी बिहार विधान सभा चुनावों को लेकर सीटों के बँटवारे का औपचारिक एलान किया। साझा प्रेस वार्ता में श्री रामविलास पासवान, श्री उपेन्द्र कुशवाहा, श्री जीतन राम मांझी और श्री सुशील कुमार मोदी समेत बिहार राजग के चारों घटक दलों के प्रमुख नेता उपस्थित थे।

प्रेस वार्ता को सम्बोधित करते हुए भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि बिहार विधान सभा चुनाव में हम दो तिहाई बहुमत हासिल करेंगे। उन्होंने कहा कि आज जद (यू) - राजद गठबंधन में बिहार जंगलराज - 2 की ओर बढ़ रहा है और जनता को इससे मुक्ति दिलाने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने कहा, जिस महागठबंधन की बात पहले की जा रही थी, वह अब टूट चुका है। इसके बाद जो गठबंधन बचा है, वह एक मजबूरी का गठबंधन है। दूसरी तरफ हमारा जो राजग का गठबंधन है वह बिहार के विकास के लिए प्रतिबद्ध गठबंधन है। श्री शाह ने श्री नीतीश कुमार और श्री लालू प्रसाद यादव को मौकापरस्त बताया। उन्होंने कहा कि भाजपा शासित राज्य तेज गति से विकास के पथ पर अग्रसर हैं, वहाँ जनता हमारी सरकार द्वारा चलाये जा रहे लोक कल्याणकारी कार्यक्रमों से संतुष्ट है और जनता का लगातार अपार जन-समर्थन हमें मिल रहा है, लेकिन बिहार अभी भी देश के अन्य राज्यों के विकास की तुलना में काफी पीछे है।

- **श्री नरेन्द्र मोदी जी के सुशासन और विकास के आधार पर हमने हरियाणा, महाराष्ट्र, झारखंड और जम्मू-कश्मीर विधान सभा चुनावों में शानदार सफलता हासिल की**
- **श्री नरेन्द्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में बिहार के समग्र विकास के लिए राजग राज्य में दो-तिहाई बहुमत की सरकार बनायेगी**
- **श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में बिहार राजग के चारों घटक दल एकजुट हैं और हम बिहार के समग्र विकास के लिए प्रतिबद्ध हैं**
- **बिहार का विकास हमारी प्राथमिकता**
- **जंगलराज और भ्रष्टाचार के साथ विकास कतई नहीं हो सकता**
- **बिहार जंगलराज - 2 की ओर बढ़ रहा है और जनता को इससे मुक्ति दिलाने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं**
- **श्री नीतीश कुमार ने बिहार के लोगों के जनादेश के साथ विश्वासघात किया है**

उन्होंने कहा कि 12 लाख करोड़ का भ्रष्टाचार करनेवाली कांग्रेस से हाथ मिलाकर नीतीश कुमार कैसे बिहार की जनता को भ्रष्टाचार मुक्त बिहार का वादा कर सकते हैं, जंगलराज और भ्रष्टाचार के प्रतीक श्री लालू यादव के साथ समझौता कर नीतीश कुमार कैसे बिहार की जनता को विकास के सपने दिखा सकते हैं। उन्होंने कहा कि जब तक भाजपा बिहार में सरकार में साथ रही, बिहार का विकास काफी तेज गति से होता रहा, लेकिन भाजपा के सरकार से निकलते ही विकास कार्यो पर रोक लग गयी, अपराध का ग्राफ बढ़ा है, विकास रुका है, जीडीपी में गिरावट आई है और कानून व्यवस्था चरमराई है। उन्होंने कहा कि श्री नीतीश कुमार ने बिहार के लोगों के जनादेश के साथ विश्वासघात किया है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार खुद को बिहार मान रहे हैं जबकि बिहार की जनता ने उनको नकार दिया है।

उन्होंने इस बात पर जोर देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी राजग के सर्वमान्य नेता हैं और श्री मोदी जी के नेतृत्व में बिहार राजग के चारों घटक दल एकजुट हैं। उन्होंने कहा कि श्री नरेन्द्र मोदी जी के सुशासन और विकास के आधार पर हमने हरियाणा, महाराष्ट्र, झारखंड और जम्मू-कश्मीर विधान सभा चुनावों में शानदार सफलता हासिल की और अब उनके कुशल नेतृत्व में बिहार के समग्र विकास के लिए राजग राज्य में दो-तिहाई बहुमत की सरकार बनायेगी। उन्होंने कहा कि हम बिहार के समग्र विकास के लिए कटिबद्ध हैं। उन्होंने कहा कि हमने पहले ही बिहार के विकास के लिए 1.65 लाख करोड़ रुपये की राशि आवंटित कर दी जिसमें 1.25 लाख करोड़ रुपये का विशेष पैकेज और पहले से चल रही योजनाओं के लिए अलग से दिए गए 40 हजार करोड़ रुपये की

राशि सम्मिलित है जो राज्य के विकास के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाती है। उन्होंने कहा कि जंगलराज और भ्रष्टाचार के साथ विकास कतई नहीं हो सकता।

उन्होंने कहा कि बिहार की जनता ने कांग्रेस को भी मौका दिया, लालू जी को भी परखा और श्री नीतीश कुमार के शासन को भी देखा, अब राजग की बारी है। हम बिहार की जनता से अपील करना चाहते हैं कि आप इस बार भाजपा-नीत राजग को बिहार में सरकार बनाने का मौका दें और हम यह आश्वस्त करना चाहते हैं कि हम राज्य के विकास के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे।

भाजपा अध्यक्ष श्री अमित शाह ने कहा बिहार राजग के चारों घटक दलों के बीच सीटों को लेकर आपसी सहमति बन गई है जिसके तहत आगामी बिहार विधान सभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 160, लोक जनशक्ति पार्टी (लोजपा) 40, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी (रालोसपा) 23 और हिन्दुस्तान अवाम मोर्चा (हम) 20 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। साथ ही हिन्दुस्तान अवाम मोर्चा के कुछ कार्यकर्ता कुछ सीटों पर भाजपा के चुनाव चिह्न पर भी चुनाव लड़ेंगे जिसका निर्णय स्वयं श्री जीतन राम मांझी जी लेंगें। उन्होंने कहा कि हम जल्द ही बिहार के विकास को लेकर अपने साझे घोषणा पत्र को लेकर आपके सामने उपस्थित होंगें। उन्होंने कहा कि बिहार का विकास हमारी प्राथमिकता है और हम बिहार को देश के विकसित राज्यों के समकक्ष लाकर बिहार को विकास के पथ पर अग्रसारित करेंगे।■

'पंच क्रांति अभियान' का शुभारम्भ

'युवाओं के कौशल विकास से होगा देश का विकास'

केंद्रीय वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली ने 17 सितंबर को भारतीय जनता युवा मोर्चा के 'पंच क्रांति अभियान' का शुभारम्भ आदरणीय प्रधानमन्त्री श्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिवस पर दिल्ली के मावलंकर सभागार में किया। कार्यक्रम में केंद्रीय वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली समेत कई केंद्रीय मंत्रियों एवं शीर्ष भाजपा नेतृत्व सम्मिलित हुआ। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के पांच प्रमुख कार्यक्रम- स्वच्छता, योग, कन्या-शक्ति, निर्माण और कौशल विकास जैसे विषयों को लेकर भाजयुमो दिल्ली समेत देश की 60 फीसदी से भी अधिक युवा जनसंख्या के बीच 'पंच क्रान्ति अभियान' चलाएगा। कार्यक्रम में समाज के विभिन्न वर्गो के लोगों को भी सम्मानित किया गया जो इन पंच क्रांतियों के 'दूत' बन कर प्रधानमंत्री के स्वप्न को पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं।

केंद्रीय वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली ने कहा कि देश में विभिन्न प्रदेशों की भांति भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बिहार में भी सरकार बनाएगी। युवा मोर्चा की प्रशंसा करते हुए श्री जेटली ने कहा कि युवाओं ने ही देश में ऐतिहासिक बहुमत देकर मोदीजी को प्रधानमंत्री बनाया था और अब देश हित में उनके द्वारा किये गए कार्यो को जन-जन तक पहुँचाने का कार्य भी युवा ही करेंगे। देश के हित में हम जी.एस.टी जैसा कानून चाहते हैं परन्तु कांग्रेस पार्टी इसका विरोध करती है और संसद नहीं चलने देती। लेकिन फिर भी हम जनहित में निरंतर कार्य करते रहेंगे। कौशल विकास से ही सही मायनों में देश का विकास होगा।

- युवाओं के कौशल विकास से होगा देश का विकास
- युवा शक्ति से होगी ''पंच क्रान्ति''
- मोदी जी के नेतृत्व में भारत बनेगा विश्वगुरु

कार्यक्रम की अध्यक्षता भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अनुराग सिंह ठाकुर ने की। कार्यक्रम में केंद्रीय खेल एवं युवा मामलों के मंत्री श्री सर्वानन्द सोनोवाल, केंद्रीय कौशल विकास राज्य मंत्री श्री राजीव प्रताप रूडी, केंद्रीय पर्यटन राज्य मंत्री श्री महेश शर्मा, भाजपा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री श्याम जाजू, राष्ट्रीय महामंत्री श्री अरुण सिंह, दिल्ली प्रदेश भाजपा अध्यक्ष श्री सतीश उपाध्याय सम्मलित हुए। समापन भाषण भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री (संगठन) श्री रामलाल ने किया। ■

संगठनात्मक गतिविधियां : पोर्ट ब्लेयर नगर निगम चुनावों में भाजपा की जीत

यह जीत प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की विकास की नीतियों और हमारी 'सबका साथ, सबका विकास' की विचारधारा की जीत है : अमित शाह

पहली बार भाजपा पोर्ट ब्लेयर नगर निगम चुनावों में अपना परचम लहराते हुए सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है और नगर निगम के 24 सीटों में से 11 पर कब्जा जमा लिया है जबकि भाजपा को पिछली बार के नगर निगम चुनावों में 18 सीटों में से केवल तीन सीटों पर विजय श्री प्राप्त हुई थी। यह पूर्णतया संभव है कि भाजपा अपने सहयोगी दलों के साथ पूर्ण बहुमत से पहली बार पोर्ट ब्लेयर नगर निगम में कांग्रेस को अपदस्थ कर अपनी सरकार बनाये।

पोर्ट ब्लेयर नगर निगम चुनावों में भाजपा को मिली ऐतिहासिक सफलता पर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह ने राज्य की जनता, भाजपा कार्यकर्ताओं तथा संगठन पदाधिकारियों को बधाई दी और कहा कि यह प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की विकास की नीतियों और हमारी 'सबका साथ, सबका विकास' की विचारधारा की जीत है। उन्होंने भाजपा में अपना विश्वास व्यक्त करने के लिए पोर्ट ब्लेयर के लोगों को भी धन्यवाद दिया।

मध्य प्रदेश, राजस्थान और बैंगलोर के निकाय चुनाव के बाद अब पोर्ट ब्लेयर नगर निगम चुनावों में लगातार चौथी जीत – यह प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा गरीबों, शोषितों और वंचितों के उत्थान के लिए चलाये गए लोक कल्याणकारी योजनाओं की जीत है।

पहले मध्य प्रदेश और राजस्थान के निकाय चुनावों में जीत, फिर बैंगलोर और अब पोर्ट ब्लेयर नगर निगम चुनावों में जीत – एक के बाद एक लगातार अभूतपूर्व जीतों पर प्रसन्नता जाहिर करते हुए भाजपा अध्यक्ष श्री शाह ने कहा कि यह जीत कांग्रेस अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी और उपाध्यक्ष श्री राहुल गांधी के लगातार गरीब विरोधी, विकास विरोधी तथा नकारात्मक आरोपों की राजनीति के खिलाफ जनता द्वारा दिया गया जनादेश है।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र की भाजपा-नीत राजग सरकार ने गरीबों, शोषितों और वंचितों के कल्याण के लिए तथा देश के सर्वांगीण विकास के लिए अनेकों कार्यक्रम चलाये हैं जिनके अच्छे परिणाम अब धरातल पर दिखने शुरू हो गए हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा और विकास एक-दूसरे के पर्याय बन चुके हैं और जनता ने भी श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा की विकास की नीतियों और सुशासन में अपनी निष्ठा जाहिर करते हुए भाजपा पर एक बार फिर से अपनी मुहर लगा दी है।

पोर्ट ब्लेयर नगर निगम चुनावों में भाजपा को मिले व्यापक जनादेश पर टिप्पणी करते हुए उन्होंने कहा कि पोर्ट ब्लेयर नगरपालिका की कांग्रेस सरकार के भ्रष्टाचार तथा उनकी गरीब और

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र की भाजपा-नीत राजग सरकार ने गरीबों, शोषितों और वंचितों के कल्याण के लिए तथा देश के सर्वांगीण विकास के लिए अनेकों कार्यक्रम चलाये हैं जिनके अच्छे परिणाम अब धरातल पर दिखने शुरू हो गए हैं।

विकास विरोधी नीतियों से जनता अपने आपको उपेक्षित और ठगा महसूस कर रही है। इसलिए जनता ने इस जीत के माध्यम से कांग्रेस को सच्चाई का आईना दिखाने का काम किया है।

उन्होंने कहा कि कांग्रेस की देश की आर्थिक प्रगति एवं विकास में बाधा उत्पन्न करने की नकारात्मक राजनीति के खिलाफ हर जगह जनता में जनाक्रोश है और जनता आने वाले समय में कांग्रेस को इसी तरह से माकूल जवाब देती रहेगी।

भाजपा अध्यक्ष श्री शाह ने कहा कि जनता की अदालत ने कांग्रेस द्वारा भाजपा के खिलाफ फैलाये जा रहे मिथ्या एवं आधारहीन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा कि देश की राजनीति में हाशिये पर खड़ी कांग्रेस को अपने इस नकारात्मक राजनीति के ऊपर गंभीर आत्मचिंतन करने की जरूरत है। ■

भारत में कारोबार के लिए गुजरात सबसे सुगम राज्य : विश्व बैंक

शीर्ष पांच में से चार स्थानों पर भाजपा शासित राज्य

भाजपा शासित गुजरात उद्योग-व्यवसाय के लिहाज से सुगमता वाले राज्यों की सूची में गुजरात शीर्ष पर है। यानी गुजरात में उद्योग-व्यवसाय लगाना-चलाना सबसे आसान है। देश के राज्यों में कारोबार में सुगमता पर पहली बार जारी इस सूची को विश्व बैंक ने तैयार किया गया है। इस रैंकिंग में भाजपा शासित राज्य शीर्ष पांच में से चार स्थानों पर काबिज हैं। भाजपा के सहयोगी तेलुगूदेशम पार्टी (टीडीपी) शासित आंध्र प्रदेश दूसरे स्थान पर रहा। इनके बाद क्रमशः झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान का स्थान है। ये सभी राज्य भाजपा शासन वाले हैं।

भाजपा शासित गुजरात उद्योग- व्यवसाय के लिहाज से सुगमता वाले राज्यों की सूची में गुजरात शीर्ष पर है। यानी गुजरात में उद्योग-व्यवसाय लगाना-चलाना सबसे आसान है। देश के राज्यों में कारोबार में सुगमता पर पहली बार जारी इस सूची को विश्व बैंक ने तैयार किया गया है। इस रैंकिंग में भाजपा शासित राज्य शीर्ष पांच में से चार स्थानों पर काबिज हैं। भाजपा के सहयोगी तेलुगूदेशम पार्टी (टीडीपी) शासित आंध्र प्रदेश दूसरे स्थान पर रहा। इनके बाद क्रमशः झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान का स्थान है। ये सभी राज्य भाजपा शासन वाले हैं।

राज्यों में व्यवसाय सुधारों के क्रियान्वयन का आकलन शीर्षक वाली रिपोर्ट विश्व बैंक ने औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग (डीआईपीपी), केपीएमजी, सीआईआई और फिक्की के सहयोग से तैयार की है। इस पूरी प्रक्रिया का मकसद कारोबार का माहौल सुधारने के लिए राज्यों के बीच प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहन देना है। साथ ही इसका उद्देश्य घरेलू और विदेशी निवेश आकर्षित करना है। इस कदम से वैश्विक कारोबार में सुगमता सूची में भारत का स्थान सुधारना है। कारोबार में सुगमता की स्थिति को और बेहतर करने पर जोर देते हुए विश्व बैंक के कंट्री निदेशक ओनो रहल ने रिपोर्ट की प्रस्तावना में लिखा है कि भारत में उद्योगों को जरूरत से अधिक नियामकीय बोझ झेलना पड़ता है। दरअसल, इस आकलन से यह तथ्य सामने आता है कि ज्यादातर राज्यों ने पहले ही महत्वाकांक्षी सुधार कार्यक्रमों को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया है। 32 राज्यों और संघ शासित प्रदेशों की यह रैकिंग आठ मानदंडों पर आधारित है। इसमें कारोबार स्थापित करना, भूमि का आवंटन, श्रम सुधार और पर्यावरण मंजूरी की प्रक्रिया जैसे मानदंडों के आधार पर राज्यों को रैंकिंग दी गई है। इसके अलावा अन्य मानदंडों में बुनियादी ढांचा, कर के लिए पंजीकरण की प्रक्रिया और विभिन्न नियमों के अनुपालन का निरीक्षण शामिल हैं। इस सूची में शीर्ष दस राज्यों में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, ओडिशा, महाराष्ट्र, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश शामिल हैं। इस सूची में मिजोरम, जम्मू-कश्मीर, मेघालय, नगालैंड और अरुणाचल प्रदेश जैसे राज्य नीचे हैं।

इस रिपोर्ट में पिछले साल मुख्य सचिवों की कार्यशाला में व्यवसाय सुगमता के लिए तय की गई 98 सूत्रीय कार्रवाई योजना को भी आधार बनाया गया है। सूची में प्रमुख राज्यों में पश्चिम बंगाल 11वें स्थान पर है। उसके बाद क्रमशः तमिलनाडु (12वें), हरियाणा (14वें), दिल्ली (15वें), पंजाब (16वें) हिमाचल प्रदेश (17वें), केरल (18वें), गोवा (19वें), बिहार (21वें) और असम 22वें स्थान पर है। दरअसल यह रिपोर्ट बेहतर तरीके से ऐसे राज्यों को खाका उपलब्ध कराती है जो कारोबारी माहौल में सुधार और रोजगार सृजन को लेकर गंभीर हैं।

उल्लेखनीय है कि बिजनेस करने के दौरान किसी कारोबारी को राज्य सरकार से कई अनुमति लेनी पड़ती है। इसमें जमीन की उपलब्धता और आवंटन सबसे अहम है। इस प्रक्रिया को राज्य जितना आसान बनायेंगे, उस राज्य में बाहरी निवेशकों की पूंजी उतनी अधिक मात्रा आयेगी। इससे राज्य के विकास पर भी अनुकूल प्रभाव पड़ता है। कई बार यह प्रक्रिया इतनी जटिल होती है कि राज्य में व्यापार करना बाहर के निवेशकों के लिए काफी मुश्किल हो जाता है। ऐसे स्थिति में निवेशक का रुझान दूसरे राज्यों की ओर बढ़ जाता है और अत्यधिक संसाधनों के रहते भी कोई राज्य गरीब बना रह जाता है। ■

सरकार की उपलब्धियां

निशक्तजनों के लिए 'स्वावलंबन स्वास्थ्य बीमा योजना'

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने निशक्तजनों को 'स्वावलम्बन स्वास्थ्य बीमा योजना' उपलब्ध कराने के लिए 21 सितंबर को न्यू इंडिया एश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड के साथ एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए। ट्रस्ट फंड फॉर इम्पॉवरमेंट ऑफ पर्सन्स विद् डिसबिलिटीज के मानद सचिव श्री अविनाश कुमार अवस्थी और न्यू इंडिया एश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड की महाप्रबंधक सुश्री नीरा सक्सेना ने निशक्तजनों के सशक्तिकरण संबंधी विभाग में सचिव श्री लव वर्मा की उपस्थिति में सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए।

निशक्तजनों को स्वतंत्रता और गरिमा के साथ जीवन बिताने तथा उन्हें सक्षम और समर्थ बनाने के लिए उन तक स्वास्थ्य सेवाओं और उनकी पहुंच की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। इस संदर्भ में, स्वास्थ्य बीमा की सुविधा बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, लेकिन वर्तमान में ऐसे बीमा उत्पाद उनको आसानी से उपलब्ध नहीं हो पाते। इस स्थिति में, 'स्वावलम्बन स्वास्थ्य बीमा योजना' की परिकल्पना दृष्टिबाधित, कम दृष्टि, कुष्ठ रोग से निजात पा चुके, सुनने में अक्षम, लोको मोटर अक्षमता, मानसिक मंदता और मानसिक रोगों से पीड़ित लोगों को किफायती स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से की गई है। इसका लक्ष्य निशक्तजनों के सामान्य स्वास्थ्य और जीवन की स्थितियों को बेहतर बनाना भी है।

यह योजना लाभार्थी को, साथ ही साथ उसके परिवार के सदस्यों (निशक्तजन, उसकी पत्नी अथवा पति और दो बच्चों तक) को समग्र कवर उपलब्ध कराने के लिए बनाई गई है। इस योजना के अंतर्गत समस्त ऐज बैंड में एकल प्रीमियम रहता है और 18 से 65 साल आयु वर्ग का कोई भी निशक्तजन जिसके परिवार की सालाना आमदनी 3,00,000 रुपये प्रति वर्ष से कम है, वह इस योजना का लाभ उठा सकता है। यह योजना पहले से मौजूद किसी स्थिति के लिए भी कवरेज उपलब्ध कराती है तथा फेमिली लोटर के रूप में 2,00,000 रुपये प्रति वर्ष का स्वास्थ्य बीमा कवर उपलब्ध कराना भी सुनिश्चित करती है।

यह योजना राष्ट्रीय संस्थानों और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के निशक्तजनों के सशक्तिकरण से संबद्ध विभाग के अंतर्गत निशक्तजनों के लिए कम्पोजिट रीजनल सेंटर (सीआरसी) की सक्रिय भागीदारी के माध्यम से लागू की जाएगी। पंजीकृत संगठन जागरुकता जगाने और नामांकन के लिए बीमा कंपनी, सामाजिक न्याय एवं आधिकारिता मंत्रालय, स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं, राष्ट्रीय संस्थानों और सभी हितधारकों के साथ संबंध स्थापित करेंगे। सहमति पत्र के अंतर्गत न्यू इंडिया एश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड अस्पतालों का एक नेटवर्क तैयार करेगी, जहां बीमित व्यक्ति को कैशलेस इलाज की सुविधा मिल सकेगी। ■

हुगली डॉक एंड पोर्ट इंजीनियर्स लिमिटेडः

संयुक्त उद्यम के जरिए कंपनी के पुनर्निर्माण को मंजूरी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में संपन्न केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में हुगली डॉक एंड पोर्ट इंजीनियर्स लिमिटेड (एचडीपीईएल) के कर्मचारियों के स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति योजना (वीआरएस) और संयुक्त उद्यम के जरिए कंपनी के पुनर्निर्माण को मंजूरी दी गई। संशोधित वीआरएस पैकेज आईडीए-2007 पर आधारित है और वेतनमान से जोड़ा गया है। संशोधित वीआरएस योजना तीन महीने के लिए खुली रहेगी और उसे एक महीने बढ़ाने का प्रावधान है। संशोधित वीआरएस लागू हो जाने के बाद निजी क्षेत्र के साथ संयुक्त उद्यम के जरिए कंपनी का पुनर्निर्माण किया जाएगा और इसमें असफलता हुई तो कंपनी का विनिवेश किया जाएगा। संशोधित वीआरएस पैकेज लागू हो जाने से एचडीपीईएल की श्रम शक्ति में बहुत कमी आ जाएगी और इससे कर्मियों की संख्या में कमी लाने में मदद मिलेगी। इसके बाद एचडीपीईएल का पुनर्निर्माण आसान हो जाएगा। मौजूदा वीआरएस पैकेज पुराने पूर्व-संशोधित वेतनमान पर आधारित है तथा संशोधित वीआरएस पैकेज के लागू हो जाने से एचडीपीईएल के स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति के इच्छुक कर्मचारियों को बेहतर सेवा निवृत्ति लाभ प्राप्त होंगे। इस निर्णय से कर्मचारियों के कल्याण को बेहतर तरीके से अंजाम दिया जा सकेगा और सरकारी खजाने में लगातार होने वाले नुकसान को रोका जा सकेगा। ■

स्मार्ट सिटी की तरह अब स्मार्ट बनेंगे गांव

मनरेगा के तहत अब 150 दिन रोजगार

सरकार ने स्मार्ट शहरों की तर्ज पर ही स्मार्ट गांव विकसित करने, स्थानीय स्तर पर लोगों को रोजगार दिलाने और ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक विकास को गति देने के उद्देश्य से श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरबन मिशन शुरू करने का निर्णय लिया है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में 16 सितंबर को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में ग्रामीण विकास मंत्रालय के इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी।

देश में स्मार्ट सिटी की तर्ज पर अब स्मार्ट गांव भी विकसित होंगे। इसके लिए केंद्र सरकार ने 16 सितंबर को 5142 करोड़ रुपये के श्यामा प्रसाद मुखर्जी ग्रामीण मिशन को मंजूरी दे दी। इसका मकसद गांव को स्मार्ट गांव में बदलना, स्थानीय स्तर पर लोगों को रोजगार, महानगरों की ओर पलायन रोकना और ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक विकास को गति देना है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में इस योजना को लेकर मंत्रिमंडल की बैठक हुई। इसमें ग्रामीण विकास मंत्रालय के प्रस्ताव को हरी झंडी दी गई।

सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री रविशंकर प्रसाद और ग्रामीण विकास मंत्री श्री चौधरी बीरेंद्र सिंह ने बताया कि देश भर में ग्रामीण-शहरी अंतर मिटाने को 2019-20 तक 300 ग्रामीण क्लस्टर बनाए जाएंगे।

श्री प्रसाद ने कहा कि इस मिशन का लक्ष्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की विकास क्षमताओं का उपयोग करना है। इससे पूरे क्षेत्र में विकास को गति मिलेगी। इन कलस्टरों से आर्थिक गतिविधियों, कौशल विकास, स्थानीय उद्यमिता के साथ ही कई सुविधाएं मिलेंगी ताकि स्मार्ट गांवों का एक क्लस्टर बन सके।

इस योजना के तहत राज्य सरकारें ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा क्रियान्वयन के लिए तैयार रूपरेखा के अनुरूप क्लस्टरों की पहचान करेंगी। उन्होंने कहा कि स्मार्ट गांव की कल्पना के तहत मिशन को मंजूरी दी गई है। पहले चरण में सभी राज्यों में कम से कम एक क्लस्टर होगा।

बड़े राज्यों में आबादी के अनुसार क्लस्टर बनाए जाएंगे। साथ ही सरकार ने यह भी कहा कि संप्रग सरकार की पूरा (ग्रामीण इलाकों में शहरी सुविधाओं के प्रावधान) योजना केवल निजी क्षेत्र तक ही सीमित थी। इसलिए वह विफल रही। ■

ग्रामीणों को मिलेगा योजना का लाभ

- **ग्रामीणों को बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा समेत बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं भी मिलेंगी**
- **इस मिशन के तहत ग्रामीण इलाके के लोगों के लिए कौशल विकास के खासा इंतजाम होंगे**
- **एक क्लस्टर की आबादी 25-50 हजार लोगों तक की होगी**
- **पहाड़ी और मरूस्थलीय क्षेत्रों में क्लस्टर पांच हजार से 15 हजार की जनसंख्या पर बनेगा**

मनरेगा के तहत अब 150 दिन रोजगार

केंद्रीय मंत्रीमंडल की बैठक में यह फैसला लिया गया कि कमजोर मानूसन के चलते सूखे की चपेट में आने वाले राज्यों में ग्रामीणों-मजदूरों को महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के तहत 100 के बजाय 150 दिन रोजगार मिलेगा। कृषि मंत्रालय ने सूखे के प्रभाव को कम करने के लिए प्रभावित क्षेत्रों में किसानों को डीजल-बीज पर सब्सिडी सहित अन्य आर्थिक मदद देने की पहले ही घोषणा कर दी है।

फिलहाल महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून (मनरेगा) के तहत गांवों में रोजगार कार्डधारकों को 100 दिन का काम उपलब्ध कराया जाता है। देश में मानसून में कमी 16 प्रतिशत पर पहुंच जाने के बाद यह निर्णय किया गया। मानसून के कमजोर रहने से खरीफ फसलें प्रभावित हो सकती हैं और इससे ग्रामीण आय पर असर पड़ेगा।

वैचारिकी : संस्मरण – दीनदयाल जयंती (25 सितंबर) पर विशेष

पं. दीनदयाल उपाध्याय : व्यक्ति और विचार

डॉ. मुरली मनोहर जोशी

डॉ. मुरली मनोहर जोशी भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रहे हैं। विचारक राजनेता के तौर पर आप सुविख्यात हैं। डॉ. जोशी ने 'मंथन' पत्रिका में हम सबके प्रेरणास्रोत पं. दीनदयाल उपाध्याय जी को याद करते हुए महत्त्वपूर्ण संस्मरण लेख लिखा था। दीनदयाल जयंती (25 सितंबर) पर हम इसे कमल संदेश में प्रकाशित कर रहे हैं। प्रस्तुत है लेख का अंतिम भाग–

एकात्म मानववाद

एकात्म मानववाद कोई एक नारे के रूप में विकसित नहीं किया गया था। यह कोई ऐसा नारा नहीं था कि ''धन और धरती बंट के रहेगी'', या ''कमाने वाला खायेगा'', इस प्रकार की कोई बात नहीं है। यह समूचे मानव-समाज का एकात्म रूप में दर्शन करने का एक अभिनव प्रयास है।

मानव-समाज क्या है? क्या यह मनष्यों का समूह मात्र है? कुछ व्यक्तियों की केवल एक भीड़ है? दैवयोग से कुछ लोग एक साथ आ गये किसी ट्रेन के डिब्बे में या होटल में, या किसी बाजार में या किसी प्रदर्शनी में, तो क्या ऐसे मनष्यों के एकीकरण को समाज की संज्ञा दी जा सकती है? या समाज की कोई निश्चित पहिचान होनी चाहिए? दीनदयाल जी ने यह बताया कि मानव-समाज एक सावयव जीवमान तत्व है, इसे आप केवल जड़ में नहीं देख सकते, वरन् जैसे मानव-शरीर को आप एक जीवमान रूप में देखते हैं, सावयव रूप में देखते हैं, मानव-समाज को भी हमें उसी रूप में देखना चाहिए। यह कितनी अटपटी सी बात है कि यदि हम किसी से पूछें कि क्या आप 'समाजवादी' हैं? और वह उत्तर दे कि 'नहीं', तो तत्काल यह समझ लिया जायेगा कि बस यह तो 'पूंजीवादी' है,

एकात्म मानववाद मानव-समाज को केवल दो ध्रुवों के बीच में या दो विचारधाराओं के बीच में ही बांट देने का समर्थक नहीं है। सारे समाज को एक भिन्न दृष्टि से देखने के कारण एकात्म मानववाद समाज-रचना का एक अत्यन्त गतिशील प्रतिमान प्रस्तुत करता है।

और यदि कोई 'पूंजीवादी' होने से इंकार कर दे तो सामान्यत: यह समझा जायेगा कि वह 'समाजवादी' है। प्रश्न है कि क्या इन दो के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं हो सकता? एकात्म मानववाद मानव-समाज को केवल दो ध्रुवों के बीच में या दो विचारधाराओं के बीच में ही बांट देने का समर्थक नहीं है। सारे समाज को एक भिन्न दृष्टि से देखने के कारण एकात्म मानववाद समाज-रचना का एक अत्यन्त गतिशील प्रतिमान प्रस्तुत करता है।

वस्तुत: हुआ यह था कि बहुत पहले हमारे देश के अनेक मूर्धन्य नेताओं का सम्पर्क यूरोपीय राजनीतिक आन्दोलनों से हुआ। ऐतिहासिक कारणों से, वे राजनीतिक आन्दोलन दो रूपों में विकसित हुए थे। फ्रांस की राज्य-क्रांति के पश्चात् जो समूचे पश्चिमी जगत में 'स्वतंत्रता, समता और बंधुता' के विचार चले, उनमें 'स्वतंत्रता' पर आग्रह करने के कारण जनतंत्र और फिर केवल स्वतंत्रता के बारे में अधिक आग्रह के परिणामस्वरूप आर्थिक क्षेत्र में शोषण की भी स्वतंत्रता को मान्य करने वाले पूंजीवाद का भी विकास हो गया। समाज का ऐसा प्रतिमान (मॉडल) विकसित हो गया, जिसमें 'समता' या 'बंधुता' तो बिल्कुल नकार दी गयी और केवल स्वतंत्रता के नाम पर अबाधित, अमर्यादित, उच्छृंखल स्वतंत्रता का जन्म हुआ। वह प्रतिमान आज भी विश्व के कुछ देशों में।

दूसरी ओर केवल 'समता' पर बहुत अधिक आग्रह करने से 'स्वतंत्रता' और 'बंधुता' आखों से ओझल कर दी गयीं। और फिर, समता में से समान वितरण, उत्पादन-प्रणालियों पर शासकीय एकाधिकार और अंततोगत्वा राजकीय तानाशाही का जन्म हो गया। किन्तु इन

दोनों ने ही 'बंधुता' नामक तत्व को आखों से पूरी तरह ओझल कर दिया। इसलिये सारे पश्चिमी जगत् में प्रधान रूप से केवल दो ही विचारधाराएं पनप सकीं और परिणामत: एक ओर 'जनतंत्रवादी-पूंजीवादी' और दूसरी ओर ''समाजवादी तानाशाही' समाज-रचनाएं विकसित होती चली गयीं।

दीनदयालजी के अनुसार इन दोनों से भिन्न एक ऐसा विकल्प भी हो सकता है जो व्यक्तियों को केवल राजनीतिक प्राणी या केवल आर्थिक प्राणी न मानकर तथा समाज को केवल किसी विशेष उत्पादन-प्रणाली का पिष्ट-पेषण करने वाला जन-समूह न मानकर, इसको एक जीवमान संकल्पना के रूप में ग्रहण करता है। इसलिये उन्होंने व्यष्टि और समष्टि के बीच में जो संबंध होना चाहिए, उसको भारतीय पृष्ठभूमि में परिभाषित करने का प्रयत्न किया। व्यक्ति क्या है? यदि पश्चिम के विचारकों से पूछा जाय तो उनके यहाँ कालक्रम से 'व्यक्ति' की भिन्न-भिन्न परिभाषा की गयी हैं। किसी ने कहा है कि व्यक्ति तो मात्र शरीर है और इसलिये यह शारीरिक एषणाओं का पुंज है। यदि आपने किसी प्रकार से भी इनकी संतुष्टि कर दी तो व्यक्ति सुखी हो जाता है। और समाज क्या है? तो उत्तर मिलेगा कि वह विभिन्न व्यक्तियों में अपनी शारीरिक एषणाओं को पूरा करने के लिये एक समझौता मात्र है। साथ आना और मिलना और फिर उसके बाद एक विशेष आर्थिक प्रणाली का जन्म लेना-यही बस समाज-जीवन है, इसके आगे है ही क्या? स्पष्ट है कि यह समाज-व्यवस्था का एकांगी प्रतिमान (मॉडल) है। कहीं विचारकों ने यह कहा कि 'व्यक्ति' मात्र एक धार्मिक अस्तित्व है, यह तो धार्मिक विचारों से अनुप्राणित होता है। संभवत: इससे कुछ कठमुल्लापन का, धार्मिक अंधविश्वासों का, मतांधता का एक विशेष दुराग्रह निर्मित हुआ और उसने भी विश्व में विनाश किया। कुछ ने कहा कि नहीं व्यक्ति तो एक राजनीतिक अस्तित्व है, इसकी कुछ विशिष्ट राजनीतिक आकांक्षाएं हैं, उनकी पूर्ति के लिये ही विभिन्न समाजों का उदय होता है इत्यादि-इत्यादि और साम्राज्यवाद उसमें से पैदा होता है।

एकात्म मानववाद के अनुसार, व्यक्ति केवल शरीर नहीं है, बल्कि भारतीय विचारकों के तारतम्य में व्यक्ति शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा का समुच्चय है। क्योंकि समष्टि व्यक्तियों से मिल कर बनती है, इसलिये उसमें भी इन तत्वों का किसी न किसी रूप में दर्शन होना चाहिए। इसलिये समष्टि के लिये भी देश, जन, संस्कृति और चिति की आवश्यकता है। व्यष्टि-समष्टि- संबंधों की इस व्याख्या में चिति को ठीक से समझना महत्वपूर्ण है।

भिन्न-भिन्न प्रकार से 'व्यक्ति' को परिभाषित करने के कारण, उसकी किसी एकांगी प्रवृत्ति को ही समग्र व्यक्ति मान लेने के कारण, अनेक प्रकार के विचार देखने में आते हैं।

फ्रायड ने भी एक प्रकार के 'व्यक्ति' को सामने रखा, उसने मानव की अधिकांश क्रियाओं और कार्य-व्यापारों का उद्गम उसकी ग्रंथियों के साथ जोड़ा और कहा कि व्यक्ति में जो वासनाएं हैं, उनसे ही वह अनुप्राणित होता है और वे ही उसे प्रेरित करती हैं। उसकी जो भी भावनाएं हैं, जो भी उसके अन्दर प्रेरणाएं है, उन सब का उद्गम व्यक्ति के यौन-व्यवहार पर निर्भर है। फ्रायड ने व्यक्ति के इस रूप पर ही बल दिया।

कहीं-कहीं 'व्यक्ति' एक आर्थिक प्राणी के रूप में ही समझा गया। तब व्यक्ति और समाज का परस्पर संबंध उत्पादन-प्रणाली के आधार पर ही समझने का प्रयत्न किया गया। तो, तरह-तरह से व्यक्ति को परिभाषित करने के प्रयत्न किये गये और उन पर आधारित अनेक राजनीतिक-आर्थिक दर्शन प्रस्तुत करने के प्रयत्न किये गये। पर वे सभी अधूरे हैं।

अब जिस प्रकार पश्चिम में जीवन-दर्शन उत्पन्न हुए हैं, जिस प्रकार एक संस्कृति का जन्म वहाँ हुआ है तो क्या वही एकमात्र संस्कृति है जो मानव-जीवन के लिये कल्याणकारी है, या उसके कुछ विकल्प भी हो सकते है? दीनदयाल जी ने वैज्ञानिक एवं दार्शनिक आधार पर एक विकल्प हमारे सामने प्रस्तुत किया। इससे पहले कि वे इस विचार के प्रत्येक पक्ष को अपनी भाषा में, अपनी वाणी में, अपनी रीति से लोकप्रिय बना पाये होते, वे काल के क्रूर प्रहार से असमय ही हमारे बीच से चले गये। आज आवश्यकता है कि हम उस एकात्म मानववाद के सभी पक्षों पर विचार करें, उस पर गहराई से चिंतन करें और यह देखें कि किस प्रकार वह आधुनिक परिप्रेक्ष्य में एक जीवन्त दर्शन के रूप में मानवीय समस्याओं का निराकरण कर सकता है।

एकात्म मानववाद के अनुसार,

व्यक्ति केवल शरीर नहीं है, बल्कि भारतीय विचारकों के तारतम्य में व्यक्ति शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा का समुच्चय है। क्योंकि समष्टि व्यक्तियों से मिल कर बनती है, इसलिये उसमें भी इन तत्वों का किसी न किसी रूप में दर्शन होना चाहिए। इसलिये समष्टि के लिये भी देश, जन, संस्कृति और चिति की आवश्यकता है। व्यष्टि-समष्टि-संबंधों की इस व्याख्या में चिति को ठीक से समझना महत्वपूर्ण है।

समाज-रचना के संबध में दीनदयाल जी की चिति की अवधारणा एक श्रेष्ठ देन है। स्थूल रूप में यदि आप कहें तो जैसे व्यक्ति का एक आत्मा है, वैसे ही समाज की भी कोई आत्मा है, उसमें भी कोई चैतन्य भाव है और इस चिति का प्रकटीकरण, इसका सम्यक् रूप से अनुभव ही किसी समाज को स्वस्थ एवं गतिमान बनाता है। यह चिति ही उसका विराट रूप प्रदर्शित करती है, यही समाज को ठीक प्रकार से नियंत्रित कर सकती है।

समाज-रचना के संबध में दीनदयाल जी की चिति की अवधारणा एक श्रेष्ठ देन है। स्थूल रूप में यदि आप कहें तो जैसे व्यक्ति का एक आत्मा है, वैसे ही समाज की भी कोई आत्मा है, उसमें भी कोई चैतन्य भाव है और इस चिति का प्रकटीकरण, इसका सम्यक् रूप से अनुभव ही किसी समाज को स्वस्थ एवं गतिमान बनाता है।

यह चिति ही उसका विराट रूप प्रदर्शित करती है, यही समाज को ठीक प्रकार से नियंत्रित कर सकती है, उसके ताप को ठीक प्रकार से नियंत्रित कर सकती है और समाज को समाज रूप में अपनी स्थिति बनाये रखने में समर्थ करती है। जैसे आत्मा एक भावात्मक संबोध है, वैसे ही चिति भी एक भावात्मक संबोध है। उसको आप यदि स्थूल रूप में पकड़ना चाहें, मुट्ठी में बंद करना चाहे, तो कठिन होगा। किन्तु बिना आत्मा के मनुष्य की कल्पना भारतवर्ष में करना तो कठिन है। इसी प्रकार समाज की भी चिति का, इस चैतन्य तत्व का, समाज के रूप में रहने। की इस नैसर्गिक इच्छा का अनुभव करना ही संभव होगा, किन्तु उसको पकड़ कर किसी एक स्थूल रूप में दिखा पाना कठिन होगा। दीनदयाल जी का यह विश्लेषण था कि इस सामाजिक चेतना को, इस चैतन्य को यदि समाज में नहीं बनाये रखा जाता तो समाज अपनी सारी मूल प्रकृति को खो बैठता है। अतएव व्यष्टि और समष्टि का नैसर्गिक संबंध परस्पर सहयोग का है। व्यक्ति के आत्मा और समाज की सामूहिक चेतना का साक्षात्कार ही सच्चा जीवन-दर्शन प्रदान करेगा।

कई बार हम लोग उनसे पूछते रहते थे कि पंडित जी, संस्कृति क्या होती है? वे बड़े ही सरल ढंग से समझा देते थे कि ''भई देखो, प्रकृति तो बिल्कुल बोधगम्य है। मनुष्य को भूख लगती है--यह उसकी प्रकृति है। दूसरे के साथ बांट कर खाना चाहिए-यह इस भूख लगने वाली नैसर्गिक प्रकृति का एक विकास है मानवीय समाज को स्वस्थ रखने के लिये, इसको ठीक रखने के लिये यही संस्कृति है। दूसरे से छीन कर खा जाओ, यह विकृति है। यदि व्यक्ति अपने आत्मा और विश्वात्मा का अनुभव करता है, तो वह संस्कृति की ओर स्वभावत: ही चल पड़ता है।'' इसलिये पंडित जी कहते थे कि व्यष्टि और समष्टि का सम्यक् संबंध होना चाहिए। व्यक्ति यदि सूक्ष्म है तो समष्टि विराट् है। व्यष्टि यदि बूंद है तो समष्टि सागर है।

शिक्षा के बारे में वे यह बताते थे कि भई, शिक्षा वह प्रणाली है, वह प्रक्रिया है, जिससे कोई समाज अपने सदस्यों को अपने अनुरूप ढालता है। इसलिये शिक्षा व्यष्टि और समष्टि का संबंध जोड़ने वाला प्रमुख तत्व है। शिक्षा वह प्रक्रिया है जिससे समष्टि अपने आप को पुनरुत्पादित करती है, अपने लिये योग्य नागरिक बनाती है और नागरिक शिक्षित होकर अपने समाज के लिये उपयोगी बनने की चेष्टा करता है तथा आवश्यकतानुसार उत्तम समाज का निर्माण भी करता है।

शिक्षा के बाद वह कर्म करता है, इसलिये वह कर्म ऐसा होना चाहिए कि व्यष्टि के प्रति उस समाज ने शिक्षा का अभी तक जो दायित्व निभाया है, उसका प्रतिफल समाज को दे सके। अर्थात् समाज ऐसी शिक्षा व्यक्ति को दे कि वह व्यक्ति उसके लिये उपयोगी इकाई बनें सके और जब व्यक्ति कर्म करेगा तो कर्मफल के रूप में उसो मिलना चाहिए।

और फिर, जैसे कि व्यक्ति कर्म भी करता है, कर्मफल भी मिलता है तो उसको यश करना चाहिए। यह भारतीय संस्कृति का एक तत्व है। समाज का हम फिर से भंडार भरें, फिर से कुछ ऐसा त्याग करें कि समाज के स्रोत सूखें नहीं और शिक्षा, कर्म एवं कर्मफल के लिये निरंतर प्रयत्नशील, समृद्ध समाज

बनता रहे-उसके लिये यज्ञ करना चाहिए और, फिर वे हंसी मजाक में कहते थे, अन्ततः आज की जो कराधान-प्रणाली है, वह क्या है? यह भी तो यज्ञ का रूप है। जो मैंने कमाया, उसका एक अंश मैं समाज के लिये दे रहा हूं। इस कराधान को क्यों नहीं आप आजकल यज्ञ के रूप में स्वीकार करते? जैसे यज्ञ एक पवित्र कार्य माना जाता है, ऐसे ही समाज को अंश प्रदान करना, समाज के स्रोतों को भरते जाना, अपनी आय में से एक अंश समाज के लिये बराबर, विधिवत देते जाना-यह यज्ञ की भावना से होना चाहिए। इसलिये कर-वंचना नहीं होनी चाहिए। समाज-रचना की व्यवस्था करने वाले इस प्रकार के प्रतिमान हम बनायें।

अर्थायाम

वे प्रायः कहते थे कि प्राणायाम की आवश्यकता पड़ती है शरीर के हर अंग में पोषक 'आक्सीजन' पहुंचाने के लिये। जीवन के लिये जो सबसे महत्वपूर्ण तत्व है- प्राणवायु, वह यदि आप शरीर के हर जीवकोष (सेल) में पहुंचाना चाहते हैं तो उसके लिये आपको प्राणायाम करना पड़ता है। उसी प्रकार से भौतिक क्रिया-कलापों के लिये पोषक तत्व ''अर्थ'' है (जिसमें उत्पादन और उपभोग दोनों ही सम्मिलित हैं), अतः समाज को अर्थायाम करना चाहिए।

प्राणायाम है नियंत्रित श्वास लेना उसको क्षणिक रोकना और फिर उसका निश्वास अर्थात् आक्सीजन लेना, रक्त के प्रत्येक कण तक पहुंचाना और दूषित वायु को बाहर निकालना। निरन्तर इस बात का प्रयत्न करना कि यह पोषण प्रत्येक जीवकोष में पहुंचता रहे। तो जैसे व्यक्ति के स्वास्थ्य के लिये यह प्राणायाम आवश्यक है, वैसे ही समाज के स्वास्थ्य के लिये 'अर्थायाम' आवश्यक है। यह स्वाभाविक है कि जैसे आप केवल सांस खींचकर ही बहुत देर तक नहीं बैठे रह सकते (समाधि वालों की बात छोड़ दीजिए, सामान्य व्यक्ति के लिये सांस रोक कर बैठना कठिन है), वैसे ही आप अर्थ को एक स्थान पर जकड़ कर नहीं बैठ सकते। यदि रक्त कहीं शरीर के एक कोने में जाकर जमने लग तो थक्के बनने लगते हैं, जीवन के लिये खतरा बन जाता है।

इसी प्रकार यदि अर्थ एक ही व्यक्ति के पास बहुत अधिक मात्रा में संचित हो जाय तो यह भी सामाजिक स्वास्थ्य के लिये प्रदूषण पैदा करता है, अवरोध उत्पन्न करता है। प्राणायाम की भांति अर्थायाम सामाजिक स्वास्थ्य के लिये आवश्यक है और इसमें से फिर उपभोग पर संयम, उत्पादन कैसा और उपभोग कितना और किस सीमा तक, ये सारे सिद्धान्त बिल्कुल स्वाभाविक रूप में प्राप्त होते चलते हैं।

इस प्रकार हम देखते हैं कि **एकात्म मानववाद किसी एक विशेष राजनीतिक नारे से नहीं बंधा है, यह विचार मानव और मानव-समाज की मूल प्रकृति के विश्लेषण पर आधारित है। शायद मनुष्य की चार मोटी विधाएं मन, बुद्धि, शरीर और आत्मा भारत में अभी तक सर्वमान्य हैं (महर्षि अरविन्द के सिद्धान्त के अनुसार यदि कभी अतिमानव का प्रादुर्भाव हुआ तो किसी अन्य विधा हो भी हम देख सकेंगे, तब शायद बात भले ही बदल जाय) और जब तक ये चार तत्व सर्वमान्य हैं, तब तक ऐसा समग्र चिन्तन, जिसमें व्यक्ति माने मन, बुद्धि, शरीर और आत्मा तथा समाज माने देश, जन, संस्कृति और चिति, जिसमें व्यष्टि और समष्टि के सम्यक् संबंध शिक्षा, कर्म, कर्मफल और यज्ञ द्वारा परिभाषित हैं, जिसमें धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के चारों पुरुषार्थों का विचार है, एक स्वस्थ समाज-रचना के लिये जीवन-दर्शन एवं विचार-दर्शन के रूप में हमारे सामने उपस्थित है।** इस एकात्म मानववाद का हम गहराई से अनुशीलन करें। इसके आलोक में अच्छे, स्वस्थ, समतामूलक समाज का निर्माण करें।

पंडित जी कहा करते थे केवल नारेबाजी से कोई काम नहीं चलेगा। जिस दिन तक उस मानव को, जो ऐसे क्षेत्रों में रहता है जहां आज प्रकाश नहीं है, जहां दरिद्रता और दैन्य का साम्राज्य है, जहाँ उसके पांव की बिवाई फटी हुई है, जिसे जूता पहिनने के लिये प्राप्त नहीं है, जिसे रोग होने पर औषधि नहीं है, उस निरक्षरा निरुत्साही और किंकर्तव्यविमूढ़ मानव को जब हम एक स्वस्थ और सुन्दर समाज का दर्शन करा सकेंगे-समय जहां अचल खड़ा है, वहां उसे जब हम गति दे सकेंगे, उस समय तक प्रत्येक विचारशील व्यक्ति को, संवेदनशील व्यक्ति को ऐसे समाज के निर्माण के लिए सतत कार्यरत रहना चाहिए।

उसके कार्यो का जो भी कुछ उपास्य है, वह वही दरिद्रनारायण, वही पीड़ित, वही शोषित मानव है, उसके उद्धार के लिये भी उत्तम प्रकार की समाज-रचना विकसित की जानी चाहिए। मैं समझता हूं कि इस तत्त्व को समझने के लिये और अच्छी, स्वस्थ, सबल, योग्य समाज-रचना के लिये एकात्म मानववाद का अनुशीलन, उस पर विचार-विमर्श करना ही शायद उनके प्रति सबसे महत्वपूर्ण श्रद्धांजलि होगी।■

-समाप्त

श्रद्धांजलि

'लाल, अब मैं नहीं लिख पाऊंगा'

ykyÑ".k vkMok.kh

'पंडित दीनदयाल उपाध्याय' के संग लंबे समय तक उनके मार्गदर्शन में काम करने का सौभाग्य प्राप्त करने वालों में एक नाम है श्री लालकृष्ण आडवाणी। आडवाणीजी भारतीय जनसंघ के तीन बार अध्यक्ष रहे। वे आपातकाल के दौरान भी जनसंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। वे भाजपा के भी तीन बार राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे। देश के उपप्रधानमंत्री रहे। संगठन-सत्ता दोनों को उन्होंने करीब से देखा है। कमल संदेश के संपादक श्री प्रभात झा ने श्री आडवाणीजी से दीनदयालजी के बारे में चर्चा की। प्रस्तुत है प्रमुख अंश :

श्री लालकृष्ण आडवाणी ने कहा कि जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर प्रतिबंध लगा था तो मैं राजस्थान में प्रचारक था। दिल्ली में उन दिनों संघ और सरकार में प्रतिबंध को लेकर वार्तालाप चल रहा था। वार्तालाप के दौरान संघ को लेकर दो आपत्तियां आ रही थीं। एक, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक गोपनीय संस्था है। दूसरा, संघ का कोई अपना संविधान नहीं है। मैंने उस समय गुरूजी के पास जाकर इन दोनों सवालों के बारे में चर्चा की। इस पर गुरूजी ने जवाब देते हुए कहा कि ब्रिटेन का कोई लिखित संविधान नहीं है और जो उसके कानून हैं, वह उसी अनुसार चलता है, तो क्या ब्रिटेन कोई गोपनीय राष्ट्र है। या फिर समाज-परिवार या संस्थान उसका भी लिखित कोई संविधान होता है। बात रही राष्ट्रीय स्वयंसवेक के संविधान की तो इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है। इस चर्चा के दौरान स्वयं एकनाथ रानाडे जी और बाबा साहब आपटे भी थे। उस समय सिंध प्रांत के प्रांत प्रचारक राजपाल पुरी थे। उन दिनों जब संघ के संविधान का कार्य चल रहा था, तो मुझे भी इस कार्य से बुलाया जाता था। उसी दौरान मा. दीनदयालजी भी आया करते थे, और मेरा भी उन्हीं दिनों से इनसे पहला परिचय आया।

आडवाणीजी एक संस्मरण सुनाते हुए बोले कि दीनदयालजी का जीवन आदर्शमय था। उनके सबसे बड़े गुण जिसने मुझे सर्वाधिक प्रभावित किया वह यह था कि 'वे' अपने बारे में कभी नहीं सोचते थे। इसी से संबंधित एक घटना का मैं सदैव जिक्र करता हूं। आर्गेनाइजर में उनका एक साप्ताहिक कॉलम ''पालिटिकल डायरी'' हम लिखवाते थे। वे उस कॉलम में देश के सम-सामयिक विषयों पर लिखते थे। आर्गेनाइजर का वह कॉलम पढ़ा जाता था। वे इसे स्वयं अंग्रेजी में लिखते थे। पंडित जी उस समय देश भर का दौरा करते थे। बहुत लोगों से उनका मिलना-जुलना होता था। मैंने उनसे आग्रह किया कि आप जब प्रवास से लौटकर आते हैं तो यात्रा-प्रवास के अनुभव आर्गेनाइजर में लिख कर दिया करें। इससे पाठकों को भी लाभ होगा और हमारे पाठक भी बढ़ेंगे।

दीनदयालजी ने प्रवास से आने के बाद एक-दो बार तो अवश्य उस तरह के यात्रा-प्रवास का वृत्तांत भेजा। उसके बाद उन्होंने नहीं भेजा। मैं एक दिन उनके पास गया और पूछा कि आपका आलेख नहीं आ रहा। उन्होंने कहा कि ''लाल मैं अब नहीं लिख पाऊंगा?'' मैं समझ गया कि आखिर दीनदयालजी क्यों नहीं लिख रहे हैं। उन्हें उस यात्रा वृत्तांत में अपने बारे में लिखना पड़ता था। वे अपने बारे में लिखना नहीं चाहते थे। वे अपनी प्रसिद्धि नहीं चाहते थे। क्योंकि उनका जीवन अपने बारे में कभी सोचने का रहा ही नहीं।

श्री आडवाणी ने बताया कि वे कालीकट अधिवेशन से आए। मैं उनसे मिलने गया। मैं अक्सर उनसे कहता रहता था कि दीनदयालजी हम आपको एक 'स्टेनो' देते हैं। वह आपके साथ रहेगा। आप ट्रेन में भी उसे कहेंगे तो वह लिखता रहेगा। फिर एक न एक व्यक्ति आपके साथ तो रहना चाहिए। हम सभी लोग प्रबंध कर देंगे। यहां तक कि जब वे मुगलसराय के लिए प्रवास पर दिल्ली से निकले थे, उस के पूर्व भी जब हम मिलने गए थे तो यही आग्रह किया था। पर उन्होंने कहा कि नहीं भाई, मैं अपना काम स्वयं कर लेता हूं और लिखने का भी स्वयं कर लूंगा।

(नोट) आज लगता है कि आडवाणी जी कितनी दूरदृष्टि रखते थे। काश! दीनदयालजी उनकी बात मान लेते। पर होनी कुछ और थी। उसे कौन रोक सकता था। ■

(साभार : अजात शत्रु)

बेटी जन्मे भी और पढ़े भी

बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ पर विशेष

डॉ. सुधा मलैया

प्रेमचन्द की एक कहानी हैं तेंतर–दो भाइयों के बाद जब तीसरी बेटी जन्म लेती है तो उसे तेंतर कहा जाता है। कुछ संकीर्ण समाजों में 'तेंतर' आज भी उपेक्षित और तिरष्कृत बेटियां हैं जहां वे जीवन पीड़ा में गुजारती हैं। समाचार पत्र के मुख्य पृष्ठ पर जब जमीन में जिन्दा गाड़ दी गई, झाड़ियों में फेंक दी गई, लावारिस छोड़ दी गई बच्ची का चित्र देखती हूँ तो एक सिहरन–सी शरीर में दौड़ जाती है। कैसी हैं वे मांए जो बेटियों को जन्म के साथ मरने के लिए छोड़ रही हैं। तेंतर कम से कम जी रही हैं पर उपेक्षित। लेकिन इन्हें तो सांस लेना भारी है। यह केवल बालिकाओं के प्रति भेदभाव मात्र नहीं है, यह स्त्री–पुरुष के घटते अनुपात का चिन्ताजनक विषय है।

भारत के सहृदय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी भारतवर्ष के अनेक प्रदेशों में बेटियों की इस दयनीय स्थिति से परिचित थे। इसीलिए प्रधानमंत्री बनने के बाद कुछ माह के भीतर ही 22 जनवरी 2015 को 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' योजना का हरियाणा के पानीपत में उद्घोष इसी का परिणाम था। शहरी क्षेत्रों के कुछ गिने–चुने संभ्रान्त परिवारों को छोड़ दें तो ग्रामीण, अर्ध शहरी और कस्बाई क्षेत्रों में आज भी बेटियों की शिक्षा को लेकर समाज के एक वर्ग में न तो जागरूकता है और न ही वे इसे अनिवार्य समझते हैं। लैंगिक समानता, भ्रूण हत्या जैसे ज्वलंत विषयों पर राज्य सरकारों द्वारा लगातार अभियान चलाने, कानून बनने और जनता के बीच काम करने के कारण स्त्री–पुरूष अनुपात कुछ क्षेत्रों में भले ही सुधर गया हो तथा कन्याओं की संख्या बढ़ने लगी हो, लेकिन सच यह है कि बेटियों की शिक्षा के प्रति अभिभावकों का रूख अभी भी नकारात्मक और रूढ़िवादी है। वे बेटियों का पढ़ना अनिवार्य नहीं समझते। यदि परिवार में पढ़ने लायक बच्चे–लड़के व लड़कियां दोनों हों, तो लड़के की शिक्षा को प्राथमिकता दी जाती हैं। 'लड़के स्कूल जाते हैं', 'लड़कियां घर का काम करती हैं।' आदि वाक्य पाठ्य पुस्तकों में वस्तु स्थिति को दर्शाते हैं। कई परिवारों में ऐसे दृश्य देखने को मिल जाएंगे जहां अवयस्क चार–पांच वर्ष की बेटी आंगन बुहार रही है और मां दुलार से बेटे को स्कूल के लिए तैयार कर रही है। बेटे के बाल ऊंछ रही है, बस्ता तैयार कर रही है, टिफिन लगा रही है, स्कूल तक छोड़ भी रही है। किसी की नजर नहीं लगे, इसीलिए अपनी आंखों का काजल डिठौना बनाकर उसके कपाल पर लगाती है। लेकिन दो आंखें लालायित सी इस दृश्य को देखती हैं, वे भी स्कूल जाने के लिए प्रस्तुत हैं। पर माता–पिता जागरूक नहीं हैं।

अटलजी की सरकार के समय नारा दिया गया– बेटी को जन्मने दें, जन्मी को जीने दें, अब इसमें यह जोड़ा गया है कि जन्मी बेटी को पढ़ने भी दें। बालिका की भ्रूण हत्या रोकना, उसे जन्मने देना, जितना आवश्यक है उतना ही महत्वपूर्ण है उसका पढ़ना भी। इसीलिए प्रधानमंत्री ने बेटियों की दुरावस्था के विरुद्ध पानीपत में जिस 'पानीपत' की घोषणा की, वह इस सदी का सबसे महत्वपूर्ण अभियान है। बेटी को बचाने के साथ–साथ, बची हुई बेटी को पढ़ाने का दायित्व भी इस समाज का है। न वह गर्भ से वंचित हो और न ही स्कूल से। प्राथमिक शिक्षा के साथ–साथ उच्च शिक्षा भी उतनी ही आवश्यक है। कुछ क्षेत्रों व राज्यों में ज्यों–ज्यों कक्षाएं बढ़ती जाती हैं कक्षा के भीतर लड़कियों का अनुपात घटता जाता है। कहां जा रही

अटलजी की सरकार के समय नारा दिया गया– बेटी को जन्मने दें, जन्मी को जीने दें, अब इसमें यह जोड़ा गया है कि जन्मी बेटी को पढ़ने भी दें। बालिका की भ्रूण हत्या रोकना, उसे जन्मने देना, जितना आवश्यक है उतना ही महत्वपूर्ण है उसका पढ़ना भी। इसीलिए प्रधानमंत्री ने बेटियों की दुरावस्था के विरुद्ध पानीपत में जिस 'पानीपत' की घोषणा की, वह इस सदी का सबसे महत्वपूर्ण अभियान है।

हैं स्कूल छोड़ने वाली ये बच्चियां, इस बात की चिन्ता भी 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' अभियान में की गई है। हरियाणा से इस अभियान का शुभारंभ करना इसलिए भी आवश्यक था क्योंकि हरियाणा में स्त्री-पुरूष अनुपात भयानक स्थिति में है। कन्या भ्रूण हत्या का ग्राफ भी इस प्रदेश में सर्वाधिक है। लेकिन अब यह अभियान सारे देश में सफल हो रहा है। माता-पिता यह समझने लगे हैं कि बेटियां भी उनके नाम को रोशन कर सकती हैं, बुढ़ापे का सहारा बन सकती हैं और देश के विकास में अपना योगदान दे सकती हैं। पहले-पहल जब प्रदेशों के 100 चुने हुए जिलों में एक राष्ट्रीय अभियान के तहत यह योजना कार्यान्वित की गई तो इसकी सफलता के विषय में थोड़ा संदेह था लेकिन राज्यों ने आगे बढ़कर इसे हाथों-हाथ लिया और बेटियों को उनका अधिकार दिलाने के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की इस पहल का स्वागत किया। प्रधानमंत्री ने अन्तर्राष्ट्रीय बालिका दिवस पर बेटियों के साथ हो रहे भेदभाव को रोकने के लिए सुझाव मांगे थे। उन्हीं सुझावों का अध्ययन कर बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ अभियान को अन्तिम रूप दिया गया। मध्यप्रदेश में यह अभियान लगभग दस वर्षों से लाडली लक्ष्मी योजना के रूप में क्रियान्वित है।

यह अभियान बालिका शिक्षा तक सीमित नहीं है बल्कि इसका दायरा बेटियों के अधिकारों का सम्मान करने और उन्हें सुरक्षा उपलब्ध कराने तक भी व्याप्त है। इस अभियान के माध्यम से उस समाज की मनोवृत्ति बदलने का प्रयास किया जा रहा है जो स्त्री शिक्षा को व्यर्थ मानता है। यह कार्य सामाजिक जागरुकता और परस्पर संवाद से ही किया जा सकता है। लेकिन इसके लिये सबसे अधिक आवश्यक है स्त्री को लेकर सामाजिक मानदंडों और मानस में प्रभावी परिवर्तन। वह इसी प्रकार की योजनाओं से आ रहा है। मध्यप्रदेश में अब कोई बेटी मात्र नहीं है, वह लाडली लक्ष्मी है। क्योंकि वर्ष 2011 में महिला साक्षरता और पुरूष साक्षरता के बीच लगभग 18 प्रतिशत का अन्तर था। जो कि अभी भी वैसा ही है। बिहार, उत्तरप्रदेश, हरियाणा, राजस्थान में यह सबसे कम है। केरल में महिला साक्षरता यद्यपि 100 प्रतिशत है, किन्तु बहुत से प्रकरण में उच्च शिक्षा और मन पसन्द विषय चुनने से स्त्रियों का हतोत्साहित किया जाता है। फिर भी बाकी देश की तुलना में यह सराहनीय है। देश में बेटी को बचाने और पढ़ाने के अभियान को कई आयाम दिये गये हैं। इसके अन्तर्गत अब ग्राम पंचायतें कन्या का जन्म होने पर परिजनों को उपहार भेजती हैं। प्रत्येक ग्राम पंचायत में कम से कम 1 दर्जन लड़कियों का जन्म दिवस मनाया जाता है। 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' की शपथ दिलाई जाती है। जिन ग्राम सभाओं का स्त्री-पुरूष अनुपात पहले से बेहतर होता है उन्हें सम्मानित किया जाता है। ये सभी उपाय प्रोत्साहन के लिये हैं। किन्तु कुछ अन्य महत्वपूर्ण कदम भी इस अभियान के अन्तर्गत उठाये गये हैं, जैसे बाल विवाह के लिये ग्राम प्रधान को जिम्मेदार मानकर कार्यवाही करना या कन्या भ्रूण हत्या रोकने के लिये अभियान स्कूल के स्तर से प्रारम्भ करते हुए महाविद्यालयों में भी चलाना। यह प्रसन्नता का विषय है कि महिला एवं बाल विकास विभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय तथा मानव संसाधन विकास मंत्रालय मिलकर समन्वय से इस अभियान को चला रहे हैं। इसीलिए यह एक क्रांतिकारी परिवर्तन का उद्घोष है।

मध्यप्रदेश में अब कोई बेटी मात्र नहीं है, वह लाडली लक्ष्मी है। क्योंकि वर्ष 2011 में महिला साक्षरता और पुरूष साक्षरता के बीच लगभग 18 प्रतिशत का अन्तर था। जो कि अभी भी वैसा ही है। बिहार, उत्तरप्रदेश, हरियाणा, राजस्थान में यह सबसे कम है। केरल में महिला साक्षरता यद्यपि 100 प्रतिशत है, किन्तु बहुत से प्रकरण में उच्च शिक्षा और मन पसन्द विषय चुनने से स्त्रियों का हतोत्साहित किया जाता है। फिर भी बाकी देश की तुलना में यह सराहनीय है। देश में बेटी को बचाने और पढ़ाने के अभियान को कई आयाम दिये गये हैं। इसके अन्तर्गत अब ग्राम पंचायतें कन्या का जन्म होने पर परिजनों को उपहार भेजती हैं।

जिस देश की बेटियां खेल से लेकर शिक्षा तक हर क्षेत्र में श्रेष्ठ प्रदर्शन कर रही हैं, उस देश में ऐसा अभियान बहुत आवश्यक है। 2014-15 के बजट में इस अभियान के लिए 100 करोड़ रु. की राशि का प्रावधान किया गया था, जिसे आगे और बढ़ाया जायेगा।

महत्वपूर्ण यह है कि यह देश की प्राथमिकताओं में सम्मिलित किया गया है। 'कुशल भारत,' 'निर्माण भारत' के साथ 'शिक्षिता भारत माता' का जयघोष शीघ्र ही भारत की पहचान होगा। ■

(लेखिका भाजपा राष्ट्रीय पत्रिकाएं एवं प्रकाशन विभाग से संबद्ध हैं)

साक्षात्कार

मुद्रा योजना का प्रमुख उद्देश्य निर्धनों को धन उपलब्ध कराना है : अनिल जैन

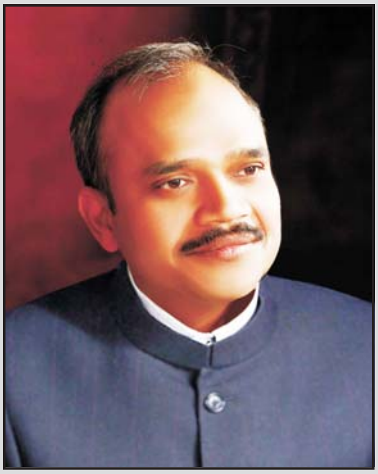

भाजपा राष्ट्रीय महामंत्री डॉ. अनिल जैन व्यवसाय से चिकित्सक हैं जिन्होंने भाजपा में कई जिम्मेदारियां सम्भाली हुई हैं। वे चिकित्सक प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय संयोजक, राष्ट्रीय सचिव और कई राज्यों के प्रभारी रहे हैं। स्पष्टवादिता के लिए ख्यात डॉ. जैन ने पार्टी के लिए अनेक चुनौतीपूर्ण कार्य किए हैं। 'कमल संदेश' के संपादक मण्डल के सदस्य रामप्रसाद त्रिपाठी के साथ साक्षात्कार में डॉ. जैन ने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के सम्बन्ध में अनेक जानकारियां दीं और स्पष्ट किया कि किस प्रकार से इससे जरूरतमंदों की सहायता हो सकेगी और भारतीय अर्थव्यवस्था उभरेगी। डॉ. अनिल जैन मुद्रा योजना के संयोजक भी हैं और उनका विश्वास है कि इससे देश में भारी परिवर्तन आएगा और 'स्किल इण्डिया' तथा 'मेक इन इण्डिया' की सफलता में इसका रचनात्मक भूमिका रहेगी। कुछ उद्धरण प्रस्तुत हैं:

– जैसा कि आप जानते हैं कि 8 अप्रैल 2015 को श्री नरेन्द्र मोदी ने मुद्रा बैंक प्रारम्भ किया है। क्या आप इस बैंक के बारे में कुछ बता सकते हैं?

सर्वप्रथम मैं कहना चाहूंगा कि 'मुद्रा' या 'माइक्रो यूनिट डेवलेपमेंट एंड रिफाइनांस एजेंसी' कोई बैंक नहीं है। यह मुद्रा योजना या प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) है, भारत के लघु उद्योगपतियों की सहायता, भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास और समृद्धि के लिए बनी है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की माइक्रो यूनिट डेवलेपमेंट एंड रिफाइनांस एजेंसी लि. (मुद्रा) 20,000 करोड़ रुपए से शुरूआत की है और 3000 करोड़ रुपए की गारण्टी रखी गई है। यह योजना सभी बैंकों में उपलब्ध है जिनमें देश के प्राइवेट बैंक भी शामिल हैं।

– मुद्रा बैंक योजना की प्रमुख उद्देश्य और उत्तरदायित्व क्या है?

मुद्रा योजना के प्रमुख उद्देश्य है– निर्धनों को धन उपलब्ध कराना। भारत के लघु उद्योगपतियों का साहूकारों के हाथों शोषण किया जाता रहा है परन्तु 'मुद्रा' उनमें एक नया भरोसा भर पाएगी ताकि देश उनके प्रयासों की सहायता देने के लिए तैयार है क्योंकि वे राष्ट्र–निर्माण में भारी सहयोग दे रहे हैं। इसके अलावा वे माइक्रोफिनांस के देनदारों और खरीददारों को नियमित भी करते हैं। तथा नियमन एवं समावेशी भागीदारी द्वारा माइक्रोफिनांस में स्थिरता लाते हैं एवं माइक्रोफिनांस इंस्टीट्यूशन को वित्त पोषण तथा क्रेडिट सपोर्ट में सहायता करते हैं, जो लघु व्यापारियों, रिटेलर्स, सेल्फ हैल्प ग्रुपों तथा व्यक्तियों को पैसा उधार देते है। ताकि वे मुद्रा योजना के उद्देश्यों को सफल बना सकें।

इस योजना के अनुसार मुद्रा बैंक की यह भी जिम्मेदारी रहेगी कि वे लघु उद्योग, वित्त पोषण कारोबारियों, एमएफआई संस्थानों के पंजीकरण, एमएफआई संस्थानों की विश्वसनीयता, उत्तरदायित्व वित्तपोषण प्रक्रिया को निर्धारित करने की जिम्मेदारी निभाएं ताकि उधार–प्रक्रिया को समाप्त किया जा सके और यह सुनिश्चित किया जाए कि समुचित ग्राहक संरक्षण सिद्धांतों और वसूली की प्रक्रियाओं, ऋणों की गारण्टी देने के लिए चलाई जा रही क्रेडिट गारण्टी योजना का निर्माण किया जा सके। यह क्रेडिट माइक्रो उद्योगों को दिया जाता रहा है और इस योजना के अन्तर्गत माइक्रो व्यापार इकाईयों को 'लास्ट माइल क्रेडिट डिलीवरी' के अच्छे निर्माण के लिए बनाया जाता है।

– ऋणों के वितरण के लिए अनेक योजनाएं हैं। यह योजना प्रारंभिक और कमजोर संस्थानों को खड़ा करने में किस तरह मददगार होगी?

भारत के ग्रामीण एवं आंतरिक भागों में रहने वाले अधिकांश व्यक्तियों को औपचारिक बैंकिंग व्यवस्था के लाभों से अलग रखा गया है। परिणामत: उन्हें बीमा, क्रेडिट, ऋण और अन्य वित्तीय साधनों तक कभी पहुंचने नहीं दिया जाता है ताकि उनसे माइक्रो-व्यापार का विकास हो सके। ऋणों पर भारी ब्याज होता है और प्राय: यह स्थिति असहनीय बनी रहती है, जिसके कारण गरीब लोग पीढ़ियों तक ऋण-जाल में फंसे रहते हैं। जब व्यापार विफल हो जाता है तो उधार लेने वाले लोगों पर उधार देने वाले लोग हावी हो जाते हैं और उनकी चालों में फंस कर उपहास का कारण बन जाते हैं। अधिकांश लोगों के पास जमीनें नहीं हैं और काम न होने के कारण उन्हें स्वयं को जीवित रखने के लिए अपनी रचनात्मकता पर निर्भर रहना पड़ता है। यदि 'मुद्रा योजना' उन्हें कुछ गाइडेंस, सहायता, प्रशिक्षण और वित्तीय सहायता प्रदान कर सके तो ये लोग आश्चर्यजनक परिणाम दे सकते हैं। दूसरे, इस योजना के अन्तर्गत समाज के सभी वर्ग ऋण के आवेदन कर सकते हैं और दूसरी प्रक्रिया बहुत ही सरल है। इस योजना के अन्तर्गत देनदारों को तीन भागों में बांटा गया है। इसमें प्रारंभिक व्यापारी, मध्यम व्यापारी और इससे आगे के विकास व्यापारी इन तीन वर्गों की समस्याओं के समाधान के लिए मुद्रा योजना में तीन ऋण इंस्ट्रूमेंट् हैं: शिशु में 50,000 तक के ऋण शामिल हैं, किशोर: में 50,000 से ऊपर के ऋण 5 लाख तक के हो सकते हैं और तरुण में 5 लाख से ऊपर तथा 10 लाख तक के ऋण हो सकते हैं। अत: योजना के इस सरल रूप होने के कारण गरीबों में यह लोकप्रिय हो सकती है।

– क्या आप समझते हैं कि इस योजना से अर्थव्यवस्था में सुधार आएगा?

देखिए, 2013 के एनएसएसओ सर्वेक्षण के अनुसार लगभग 5.77 करोड़ लघु व्यापार इकाईयां हैं, जिनमें से अधिकांश व्यक्तिगत स्वामित्व में चलती हैं जिनमें ट्रेडिंग, मैन्युफैक्चरिंग, रिटेल और अन्य लघु गतिविधियां चलती रहती हैं। अब इनकी तुलना संगठित क्षेत्र और बड़ी कम्पनियों से कीजिए जो 1.25 करोड़ व्यक्तियों को रोजगार देती हैं। स्पष्टत:, इन माइक्रो व्यापार को संभालने और पोषण करने की क्षमता विशाल है और सरकार इस बात को पहचानती भी है।

आज, यह वर्ग अत्यंत अनियमित है और संगठित वित्तीय बैंकिंग व्यवस्था से कोई वित्तीय मदद नहीं मिल पाती है।

दूसरे, अधिकांश माइक्रो उद्योग, रिटेल या ट्रेडिंग गतिविधियां शुरू की जाती है और समाज के आर्थिक कमजोर वर्गों या महिलाओं द्वारा नियंत्रित रहती हैं और इनमें टैक्नॉलाजी का इस्तेमाल नहीं हो पाता है, न ही किसी प्रकार की औपचारिक प्रशिक्षण या अन्य किसी प्रकार की बैंकिंग सहायता मिल पाती है। अब, जरा देखिए, यदि 'मुद्रा' से कोई मार्गदर्शन, सहायता, प्रशिक्षण और वित्तीय सहायता मिल जाए तो भारतीय अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करने की बड़ी संभावनाएं बन जाती है।

– क्या आप समझते हैं कि 'मुद्रा' भारत में कोई बड़ा भारी परिवर्तन कर सकती है?

निश्चित ही, यह बड़ा भारी परिवर्तन कर सकती है। यह 'स्किल इण्डिया' की सफलता में रचनात्मक योगदान कर सकती है। इस योजना के अन्तर्गत लोगों को स्वयं-रोजगार मिल सकता है और कई अनेक लोगों के लिए रोजगार जुटाया जा सकता है। दीर्घकाल में, देश में भारी बेरोजगारी संकट के लिए यह एक अच्छा जवाब सिद्ध हो सकती है। दूसरे, मुद्रा बैंक एक नए उद्योगपतियों को जन्म दे सकती है, जिनमें से कुछ एक नई ऊंचाईयों तक पहुंच सकते हैं। अत: इस छोटे से कदम से भारत की बहुत सी संकटपूर्ण समस्याओं का समाधान हो सकता है और अर्थव्यवस्था को नई जिंदगी मिल सकती है तथा अन्तत: सामान्य वर्ग के लोगों को इसका लाभ मिल सकता है।

– क्या आप समझते हैं कि भाजपा एक संगठन के रूप में इस योजना को लोकप्रिय बनाने में कोई भूमिका निभा सकती है?

मुद्रा जैसी योजनाएं समाज के अपवंचित वर्ग पर अपना ध्यान लगातार रखती रहेगी और देश के आंतरिक भागों में इसकी पहुंच बनी रहेगी। दूसरे, केन्द्र सरकार द्वारा लिए गए उपायों से इन व्यापारों से दस गुणा अधिक नौकरियां मिलने की उम्मीद है जिन्हें इस समय बड़ी व्यापारिक कम्पनियां पैदा करती हैं।

अत:, हमने भाजपा कार्यकर्ताओं तथा अन्य लोगों से अपने-अपने क्षेत्रों में इन कल्याणकारी योजनाओं को लोकप्रिय बनाने के लिए कहा है ताकि जरूरतमंद लोगों को ऋण मिल सके। ■

चंडीगढ़, सहारनपुर तथा ऋषिकेश रैली

संसद की कार्यवाही में बाधा लोकतंत्र की आत्मा के खिलाफ है : नरेंद्र मोदी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 11 सितंबर को तीन राज्यों में चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश के सहारनपुर और उत्तराखंड के ऋषिकेश में विभिन्न जन-सभाओं को सम्बोधित किया और गरीब एवं विकास विरोधी और नकारात्मक राजनीति करने के लिए कांग्रेस पर तीखा हमला किया।

प्रधानमंत्री ने चंडीगढ़ में अंतर्राष्ट्रीय हवाई टर्मिनल का उद्घाटन किया और चंडीगढ़ की नई हाउसिंग स्कीम की भी शुरुआत की। इसके बाद उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च (पीजीआईएमईआर) के 34वें दीक्षांत समारोह में छात्रों को संबोधित किया। बाद में चंडीगढ़ में आयोजित रैली में ओआरओपी पर बोलते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि हमने पिछले लोक सभा चुनाव के दौरान किये गए वादे को सत्ता में आने के साथ ही अमल में लाने का कार्य प्रारंभ कर दिया था। उन्होंने इस मुद्दे पर कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि ओआरओपी के मुद्दे के हल हो जाने के बाद भी कुछ लोग परेशान हैं क्योंकि कुछ लोगों को आंदोलन करने की बीमारी होती है।

उन्होंने कहा कि उन्हें लगता है कि मोदी ने यह मुद्दा हल कर दिया है तो हमारे लिए अब क्या काम बचा है? उन्होंने कहा कि पूर्ववर्ती सरकारों ने इस मामले को गंभीरता से नहीं लिया और पिछली सरकार ने इसके लिए केवल 500 करोड़ रुपये जारी किये लेकिन जब हमने इस पर सोचना शुरू किया तो इसके लिए अतिरिक्त राशि की जरूरत महसूस हुई और हमने इसके लिए 10 हजार करोड़ रुपये आवंटित किये।

संसद के न चलने देने को लेकर कांग्रेस के रवैय्ये पर करारा प्रहार करते हुए श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि केवल 40 लोग संसद में जिस तरह संसद की कार्यवाही को बाधित करने की कोशिश कर रहे हैं, वह लोकतंत्र की आत्मा के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि देश को यदि विकास के राह पर अग्रसर करना है तो संसद चलना जरूरी है। जन-सभा को सम्बोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं इस मामले को लोक सभा के बजाय जन-सभा में रख रहा हूँ क्योंकि जन-सभा लोक सभा से बड़ी होती है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि किसानों को मुआवजा देने में कोताही नहीं बरती जाएगी। उन्होंने कहा कि जब तक हिंदुस्तान के गांव सक्षम नहीं होंगे, देश का विकास नहीं हो सकता। श्री मोदी ने कहा कि किसानों की समस्याओं का हल उनकी प्राथमिकता है।

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने सहारनपुर में अपने अल्प-ठहराव के दौरान जनसंवाद कार्यक्रम में कहा कि हम काम करने में विश्वास करते हैं। उन्होंने कहा कि हमने वन रैंक वन पेंशन देने का वायदा पूरा किया और अब गन्ना किसानों की बारी है और उनको उनका उचित हक मिलेगा। कांग्रेस द्वारा संसद के अंदर लोकतंत्र पर सवाल खड़े करने की कोशिश पर तीखा हमला करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस लगातार संवैधानिक मूल्यों का हनन करती जा रही है लेकिन वे जितना कीचड़ उछालेंगे, कमल उतना ही खिलेगा। उन्होंने संसद में गतिरोध उत्पन्न करने की कांग्रेस की गरीब और विकास विरोधी रणनीति की निंदा की।

उन्होंने कहा कि यह कांग्रेस की नकारात्मक राजनीति का ही नतीजा है कि 400 सीटों वाली कांग्रेस 40 सीटों पर सिमट कर रह गयी है। उन्होंने भाजपा कार्यकर्ताओं का आह्वान करते हुए कहा कि वे केंद्र सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का प्रचार करें और इसे जन-जन तक पहुँचाएं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड की देवभूमि ऋषिकेश में भाजपा कार्यकर्ताओं को सम्बोधित करते हुए कहा कि अगले चुनाव में कांग्रेस इतिहास बन जाएगी। उन्होंने कहा कि अभी तक 18000 गाँवों में बिजली नहीं पहुँची है और हमने अगले एक हजार दिनों में बिजली को हर गाँव तक पहुँचाने का प्रयास प्रारंभ किया है। उन्होंने कहा कि 2022 में जब देश की आजादी के 75 साल होंगे तो देश में 24 घंटे बिजली होगी। ■

वाराणसी प्रवास

कांग्रेस ने जो कार्य 50 वर्षों में नहीं किया, वो मैं 50 महीनों में करके दिखाऊंगा : मोदी

काशी के विकास के लिए 572 करोड़ रुपयों की घोषणा

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 18 सितंबर को अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी से देश भर में विकास की गति तेज करने को दो बड़े फैसले किए। उन्होंने पब्लिक व प्राइवेट सेक्टर के साथ पर्सनल सेक्टर को भी विकसित करने के एलान के साथ 45 हजार करोड़ रुपये की इंटीग्रेटेड पावर डेवलपमेंट स्कीम (आइपीडीएस) का शुभारंभ भी किया। काशी से ऊर्जा क्रांति का आगाज करते हुए उन्होंने वर्ष 2022 तक सुदूर गांवों तक 24 घंटे और 365 दिन निर्बाध बिजली आपूर्ति कराने का वादा किया और कुल सात योजनाओं की शुरुआत की।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 18 सितंबर को अपने लोक सभा क्षेत्र वाराणसी के एक दिवसीय दौरे के दौरान अनेक लोक कल्याणकारी योजनाओं का शुभारम्भ किया और काशी के विकास के लिए 572 करोड़ रुपयों के निधि की घोषणा की। इस दौरान उन्होंने लोगों की समस्याओं से जुड़े कई मुद्दों पर बात की और लोगों को सम्बोधित किया। उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत करते हुए कहा कि ज्ञान का प्रकाश देने वाली नगरी वाराणसी आज ऊर्जा का प्रकाश देने जा रही है और काशी को स्मार्ट सिटी बनाने की यह पहली शुरुआत है।

उन्होंने कहा कि आजादी के 75वें वर्ष पर स्वतंत्रता सेनानियों को सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि देश के दूर-दराज के इलाकों में भी 24 घंटे, साल के 365 दिन बिजली की उपलब्धता हो। प्रधानमंत्री ने निराश शिक्षामित्रों से आत्महत्या जैसे कदम न उठाने की अपील की। उन्होंने कहा कि आप अपना हौसला न खोएं। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि मैंने उत्तर प्रदेश सरकार से बात की है, आप एक बार न्यायालय का आदेश आ जाने दीजिए, हम आपके साथ कोई अन्याय नहीं होने देंगे।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कौशल विकास की जरूरत पर बल देते हुए कहा कि भारत में 65 फीसदी जनसंख्या

35 साल से कम है और यदि इन हाथों में कौशल हो तो हम पूरी दुनिया के सामने मजबूती से खड़े हो सकते हैं। उन्होंने साक्षात्कार में होने वाले भ्रष्टाचार पर बोलते हुए कहा कि एक स्तर तक के पदों पर नौकरियों में साक्षात्कार बंद होना चाहिए।

विश्व भर में योग को मिलने वाले सर्वमान्य स्वीकृति के ऊपर प्रधानमंत्री ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को स्वीकार करने का मतलब दुनिया का भारत से जुड़ना है और आज पूरा विश्व भारत की तरफ आशा और गर्व के साथ देख रहा है। गंगा की सफाई को मिशन की संज्ञा देते हुए श्री मोदी ने कहा कि गंगा की सफाई के लिए राज्य सरकारों को विशेष कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि गंदगी को रोकने के लिए राज्य सरकारों को अगर जुर्माना लगाना पड़े तो लगाना चाहिए तथा सीवर का पानी गंगा में जाने से रोका जाना चाहिए। उन्होंने गंगा सफाई के लिए मां अमृता आनंदमयी द्वारा 100 करोड़ रुपयों के दान के लिए उनकी तारीफ की।

उन्होंने विकास की गति में पर्सनल सेक्टर की जरूरत बताते हुए कहा कि पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर के

ट्रैक पर ही आर्थिक विकास की गाड़ी दौड़ा पाना मुमकिन नहीं है, अतः इसमें पर्सनल सेक्टर को भी जोड़ा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि पर्सनल सेक्टर भारत के लिए बहुत बड़ी ताकत बन सकता है और इसके लिए उसे पैसा, तकनीक, कौशल और व्यापार का अवसर उपलब्ध कराया जाना चाहिए। उन्होंने अपना पूर्ण विश्वास व्यक्त करते हुए कहा कि यह क्षेत्र हिंदुस्तान को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा, मुझे पूरा विश्वास है और हमें इसी वर्ग को मुद्रा बैंक के जरिए मजबूत बनाना है।

इससे पहले एसईडीबीआई के कार्यक्रम में बोलते हुए श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि पिछले 60 साल में गरीबों के कल्याण के लिए सुबह-शाम गरीबों का नाम जपने की जो परंपरा बनी है, हमें इस परंपरा से बाहर आने की जरूरत है और हमें गरीबों को साथ लेकर सबका विकास करना होगा। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर प्रहार करते हुए कहा कि आपने जो कार्य 50 वर्षों में नहीं किया, वो मैं 50 महीनों में करके दिखाऊँगा। प्रधानमंत्री ने सरकार द्वारा गरीबों और पिछड़ों के जीवन के उत्थान के लिए सरकार द्वारा उठाये गए कदमों के बारे में बात करते हुए कहा कि हमने प्रधानमंत्री जन-धन योजना, जीवन बीमा योजना, जीवन सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना जैसे अनेक कार्यक्रम चलाये हैं जिसका सबसे ज्यादा फायदा उन्हें ही मिलेगा।

प्रधानमंत्री ने कहा कि छोटे-मोटे धंधों से जुड़े देश के लाखों निजी कारोबारियों के लिए हमने मुद्रा बैंक की शुरुआत की है जो देश के करोड़ों लोगों का भाग्य बदल सकती हैं। उन्होंने कहा कि मुद्रा बैंक की योजनाओं के तहत उन्हें बिना गारंटी के एक फीसद माह की दर पर ऋण मिलेगा ताकि वह सफल उद्यमी बन सकें और देश के आर्थिक विकास में अपना अहम योगदान दे सकें। उन्होंने विपक्षी पार्टियों पर करारा प्रहार करते हुए कहा कि जिन्होंने गरीबों के लिए कुछ नहीं किया, आज वो हमसे सवाल कर रहे हैं।

उन्होंने गरीबी से लड़ने और उस पर विजय प्राप्त करने में शिक्षा के योगदान को अहम बताते हुए कहा कि शिक्षा गरीबी से लड़ने का सबसे बड़ा हथियार है। उन्होंने लोगों से अपनी संतानों को शिक्षित करने की अपील की। प्रधानमंत्री ने काशी में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 101 ई-रिक्शा और 501 साईकिल रिक्शा का भी वितरण किया।

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के संबोधन की मुख्य बातें

- आजादी के 75वें वर्ष पर स्वतंत्रता सेनानियों को सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि देश के दूर-दराज के इलाकों में भी 24 घंटे, साल के 365 दिन बिजली की उपलब्धता हो।
- अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को स्वीकार करने का मतलब दुनिया का भारत से जुड़ना है।
- आज पूरा विश्व भारत की तरफ आशा और गर्व के साथ देख रहा है।
- कांग्रेस ने जो कार्य 50 वर्षों में नहीं किया, वो मैं 50 महीनों में करके दिखाऊँगा।
- हमें गरीबों को साथ लेकर सबका विकास करना होगा।
- जिन्होंने गरीबों के लिए कुछ नहीं किया, आज वो हमसे सवाल कर रहे हैं।
- शिक्षा गरीबी से लड़ने का सबसे बड़ा हथियार है।
- शिक्षामित्र अपना हौसला बनाये रखें।

प्रधानमंत्री द्वारा वाराणसी में वित्तीय समावेश पहल का शुभारंभ

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 18 सितंबर को वाराणसी में महत्वपूर्ण वित्तीय सहायता कार्यक्रमों की शुरूआत की। इस कार्यक्रम के तहत 101 ई-रिक्शा, 501 पैडल रिक्शा और हाथगाड़ी वितरित किए गए। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री जन-धन योजना के तहत लाभकर्ताओं को बैंक खाते और रुपे कार्ड वितरित किए गए। इस योजना के तहत दिए जा रहे ई-रिक्शा डिजिटल उपकरणों जैसे जीपीआरएस और कैमरे से लैस हैं।

इन कार्यक्रमों के लिए विभिन्न वित्तीय संस्थाओं जिसमें सिडबी, आईडीबीआई बैंक, यूको बैंक और अमेरिकन इंडिया फाउंडेशन के बीच समन्वित प्रयास किए गए। कार्यक्रम के दौरान इन संगठनों के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे। इस अवसर पर अपने संबोधन में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि इस कार्यक्रम से एक शुरूआत हुई है जिससे वाराणसी के लोगों के भाग्य में बदलाव आएगा। उन्होंने कहा कि गरीबी को खत्म करने के लिए काफी कुछ कहा गया है, लेकिन इन प्रयासों से कई दशकों तक पर्याप्त परिणाम नहीं मिले हैं। हमें गरीबी का उन्मूलन करने के लिए इन कार्यक्रमों की गति और स्तर बढ़ाने की आवश्यकता है। निर्धन व्यक्ति अपनी आने वाली पीढ़ियों का जीवन स्तर सुधारने के लिए कठिन परिश्रम करने के लिए तैयार है। इस संबंध में केन्द्र सरकार कौशल विकास पर विशेष ध्यान दे रही है, ताकि निर्धनों को आत्मनिर्भर बनाया जा सके।■

दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव

फिर लहराया विद्यार्थी परिषद् ने जीत का परचम

दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् ने लगातार दूसरे साल केंद्रीय पैनल के चारों पद जीतकर अपना परचम लहरा दिया। इस चुनाव में छात्रों ने कांग्रेस की छात्र शाखा एनएसयूआई और आम आदमी पार्टी के संगठन छात्र युवा संघर्ष समिति की नकारात्मक राजनीति को खारिज कर दिया और इन दोनों संगठनों की करारी हार हुई। अभाविप की यह जीत राष्ट्रवादी विचारधारा और मोदी सरकार के विकास के एजेंडे की जीत है। केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई योजनाओं - मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया - से युवा उत्सााहित हैं और वह बड़ी संख्या में राष्ट्रवादी विचारधारा की ओर आकर्षित हो रहे हैं।

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् (अभाविप) ने 12 सितंबर को दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव में सभी चारों सीटों पर जीत हासिल की। अभाविप के उम्मीदवारों ने अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव और संयुक्त सचिव के पद जीत लिए। गौरतलब है कि चारों सीटों पर अभाविप उम्मीदवार 4500 से अधिक वोटों के अंतर से जीते। अभाविप ने पिछले साल भी सभी चारों पदों पर जीत हासिल की थी। बौद्ध अध्ययन में एमए के छात्र श्री सतिंदर अवाना ने 6,327 मतों के अंतर से अध्यक्ष पद पर जीत हासिल की। श्री अवाना को 20,439 मत प्राप्त हुए। उन्होंने एनएसयूआई के श्री प्रदीप विजयरान को हराया। श्री प्रदीप को 14,112 वोट मिले हैं। उपाध्यक्ष पद पर कानून के छात्र श्री सन्नी डेढ़ा ने 7,570 वोटों से जीत हासिल की। उन्होंने आम आदमी पार्टी की छात्र शाखा, छात्र युवा संघर्ष समिति (सीवाईएसएस) की गरिमा राणा को हराया। एमए बौद्ध अध्ययन के छात्र श्री छतरपाल यादव ने संयुक्त सचिव पद पर 6,065 वोटों से जीत हासिल की है। एनएसयूआई के उम्मीदवार तीन पदों पर दूसरे स्थान पर रहे। सीवाईएसएस के अध्यक्ष उम्मीदवार चौथे स्थान पर रहे और उपाध्यक्ष उम्मीदवार दूसरे स्थान पर।

जेएनयू में भी लहराया भगवा

दिल्ली विश्वविद्यालय छात्रसंघ के बाद जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय छात्र संघ में भी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् ने भगवा लहराया। संयुक्त सचिव की सीट पर अभाविप ने जीत दर्ज की और श्री सौरभ कुमार शर्मा संयुक्त सचिव चुने गए। जेएनयू छात्रसंघ में 14 साल बाद अभाविप ने किसी सीट पर जीत हासिल की।

विद्यार्थी परिषद् की जीत मोदी जी के प्रति समर्थन का प्रतीक : अमित शाह

दिल्ली विश्वविद्यालय छात्रसंघ-जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव में विद्यार्थी परिषद् की जीत पर भाजपा अध्यक्ष श्री अमित शाह ने कहा कि दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ में अभाविप की सभी सीटों पर जीत राष्ट्रीय स्तर पर युवाओं के बीच मोदी सरकार की नीतियों की स्वीकार्यता को प्रदर्शित करती है। उन्होंने कहा कि दिल्ली विश्वविद्यालय और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय मिनी इंडिया है क्योंकि यहां देश भर से छात्र आते हैं। उन्होंने कहा कि दोनों संस्थाओं में इसकी जीत से राजग सरकार की सबका साथ, सबका विकास तथा अंत्योदय की राष्ट्रवादी नीतियों के प्रति लोगों का समर्थन प्रदर्शित हुआ है। श्री शाह ने कहा कि डीयू और जेएनयू मिनी भारत है क्योंकि देश के सभी क्षेत्रों से छात्र यहां अपने सपने साकार करने आते हैं। इसलिए यह जीत भारत के युवाओं की सोच को प्रदर्शित करती है।■

अभाविप के पदाधिकारियों की प्रधानमंत्री से मुलाकात

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के पदाधिकारियों ने प्रधानमंत्री से शुभेच्छा मुलाकात की। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह भी उपस्थित थे। दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र संघ के चुनाव में विजेता चारों विद्यार्थी नेता एवं जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय के छात्र संघ के के चुनाव के विजेता विद्यार्थी नेता ने भी प्रधानमंत्री से मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने सभी विजेताओं को जीत की बधाई दी और शुभकामनायें प्रेषित की। मिलने वाले पदाधिकारियों में श्री श्रीहरि बोरीकर, श्री श्रीनिवास, श्री कृष्ण कांत बोरा, श्री अतुल कुलकर्णी शामिल थे। ■

'मन की बात' का एक साल पूरा

देश में 30 लाख लोगों ने गैस सब्सिडी छोड़ी : प्रधानमंत्री

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 20 सितंबर को रेडियो कार्यक्रम 'मन की बात' के दौरान कहा कि मैंने इस कार्यक्रम के जरिए बहुत कुछ हासिल किया है। उनका कहना था कि मन की बात कार्यक्रम में अपील करने के बाद ही देश में 30 लाख लोगों ने गैस सब्सिडी छोड़ दी है। उन्होंने इसे साईलेंट रिवॉल्यूशन करार भी दिया है। सिर्फ अमीर लोगों ने ही नहीं आम लोगों ने भी सब्सिडी छोड़ दी है जिससे पता चलता है कि लोग अपनी जिम्मेदारी समझ रहे हैं। प्रधानमंत्री ने इस दीवाली पर लोगों को खादी को अपने घर में जगह देने को कहा और साथ ही उन्होंने मिट्टी के दिए जलाने की सलाह भी दी।

गौरतलब है कि प्रधानमंत्री श्री मोदी के अपील का नतीजा है कि खादी के कपड़ों की बिक्री दोगुना हो गई है और ये एक बड़ी उपलब्धि है। प्रधानमंत्री ने खादी के बढ़ते कारोबार के लिए लोगो को शाबाशी भी दी और कहा कि दिवाली पर लोगों को अन्य कपड़ों के साथ खादी के लिए भी जगह बनानी होगी। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि देश के 55 हजार लोगों ने फोन किये। लोगों नें फोन पर सुझाव और संदेश दिये। जनता के सुझाव और संदेश अहम हैं। 90 प्रतिशत में अधिक लोगों ने बहुत अच्छे सुझाव दिये।

प्रधानमंत्री ने 1965 के युद्ध का जिक्र करते हुए कहा शौर्याजलि ने इतिहास को जिंदा कर दिया। इतिहास बनाने के लिए इतिहास की बारिकियों

को समझना जरुरी है। एक छोटे बच्चे ने स्वच्छता के लिए अहम संदेश दिया। संसद में देश के स्वच्छता के लिए चर्चा हो रही है। श्री मोदी ने कहा कि महात्मा गांधी ने कहा, पहले स्वच्छता, आजादी बाद में। स्वच्छता अभियान को हर कीमत में आगे बढ़ाना है। महापुरुषों की विचारधारा का मूल्यांकन करना हमारा काम नहीं है। सभी महापुरुषों से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए।

प्रधानमंत्री श्री मोदी ने मन की बात कार्यक्रम के एक साल पूरे होने पर खुशी जताई। उन्होंने अपार स्नेह देने के बदले नागरिकों का आभार व्यक्त किया। मन की बात में प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि सेल्फी विद डॉटर मुहिम से बेटियों को गरिमा मिली। श्री मोदी ने हैंडलूम को भी अपने जीवन का हिस्सा बनाने की अपील की और कहा कि लोग मिल-जुलकर 2019 तक स्वच्छता मिशन को पूरा करें। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने बताया कि जनशक्ति में उनका अपार विश्वास है। उन्हें देश के जवानों से मिलकर प्रेरणा और ऊर्जा मिलती है और बच्चों में विज्ञान के प्रति जिज्ञासा होनी चाहिए। श्री मोदी ने कहा कि इस साल की मई में कोलकाता गया था। नेताजी के परिवार से मिला। नेताजी के परिवार के सभी सदस्यों को दिल्ली बुलाया हूं। खुशी है अक्टूबर में नेताजी के परिवार से मिलूंगा। ■

परक्राम्य लिखत (संशोधन) अध्यादेश, 2015 के क्रियान्वयन को मंजूरी

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में संपन्न केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में परक्राम्य लिखत (संशोधन) अध्यादेश, 2015 के क्रियान्वयन को मंजूरी दे दी गई। परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 (नेगोशियेबल इंस्ट्रूमेंट ऐक्ट) के प्रस्तावित संशोधन में, अधिनियम की धारा 138 के तहत किए जाने वाले अपराधों के मद्देनजर मुकदमा दायर करने संबंधी न्यायाधिकार क्षेत्र के मुद्दों पर स्पष्टीकरण शामिल हैं। चेक बाउंस हो जाने के बारे में मुकदमों से संबंधित मुद्दों के न्यायाधिकार क्षेत्र के विषय में स्पष्टीकरण के तहत चेक की एक वित्तीय उपकरण के रूप में मान्यता में इजाफा होगा। इससे आमतौर पर व्यापार और वाणिज्य को मदद मिलेगी और बैंकों सहित ऋण संस्थानों को अनुमति मिलेगी कि वे अर्थव्यवस्था में वित्त पोषण को बढ़ा सकें। अब इन संस्थानों को यह खतरा नहीं रहेगा कि कर्ज चुकाने के लिए चेक बाउंस की घटना से उन्हें हानि होगी। ■

इंडिया टीवी का बिहार चुनाव मंच कार्यक्रम

बिहार के सर्वांगीण विकास के लिए हम कटिबद्ध हैं : अमित शाह

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह ने 22 सितंबर को इंडिया टीवी के बिहार चुनाव मंच के समापन सत्र को सम्बोधित किया और कहा कि बिहार के सर्वांगीण विकास के लिए हम कटिबद्ध हैं।

- **बिहार के विकास के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा राज्य को दिए गए 1.65 हजार करोड़ रुपये का पैकेज, राज्य के विकास के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाती है**
- **मुझे पूर्ण विश्वास है कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के कुशल नेतृत्व में बिहार के समग्र विकास के लिए हम राज्य में दो-तिहाई बहुमत की सरकार बनायेंगें**
- **हमारी राजनीति और परम्परा ही विकास की रही है**
- **मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि इस बार बिहार चुनाव विकास के मुद्दे पर लड़े जाएंगे**
- **हम बिहार में एक 'लोक-कल्याणकारी राज्य' की अवधारणा को स्थापित करने वाली सरकार लाने के लिए प्रतिबद्ध हैं**
- **बिहार में विकास की अपार सम्भावनाएँ हैं**
- **राजद और जद (यू) का अलोकतांत्रिक गठबंधन केवल सत्ता प्राप्ति के उद्देश्य से किया गया एक पूर्णत: अनैतिक गठबंधन**

श्री शाह ने कहा कि हम यूँ ही नहीं विकास की बात करते हैं, बल्कि हमने हर जगह, जहां भी हमारी सरकारें हैं, विकास करके दिखाया है और वहाँ जनता हमारी सरकार द्वारा चलाये जा रहे लोक कल्याणकारी कार्यक्रमों से संतुष्ट है तथा जनता का लगातार अपार जन-समर्थन हमें मिल रहा है। उन्होंने कहा कि इसी का परिणाम है कि हमें उन राज्यों में बार-बार जनादेश मिलता है चाहे वह गुजरात हो या मध्य प्रदेश, चाहे वह राजस्थान हो या छत्तीसगढ़ या फिर गोवा। भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के कुशल नेतृत्व में हमने समान रूप से गरीबों, दलितों, शोषितों, पिछड़ों - समाज के सभी वर्गों के कल्याण के लिए काफी सराहनीय कार्य किया है। उन्होंने कहा कि हमारी राजनीति और परम्परा ही विकास की रही है। उन्होंने कहा कि मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि इस बार बिहार चुनाव विकास के मुद्दे पर लड़े जाएंगे।

उन्होंने कहा कि श्री मोदी जी ने बिहार के विकास के लिए, बिहार के गरीबों, दलितों, पिछड़ों और अति पिछड़ों के उत्थान के लिए, बिहार में सड़क, बिजली, उद्योग और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए राज्य को 1.25 लाख करोड़ रुपये का पैकेज दिया जो पहले से चल रही योजनाओं के लिए दिए गए 40 हजार करोड़ रुपये के अतिरिक्त है, जो राज्य के विकास के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाती है। उन्होंने कहा कि फिर भी आप विरोध की राजनीति करते हैं, आपके पास बिहार के सम्मान की खातिर दिए गए पैकेज के लिए श्री नरेन्द्र मोदी का धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए दो शब्द भी नहीं है? उन्होंने कहा कि बिहार को एक ऐसे समर्पित सरकार की जरूरत है जो केंद्र से कंधे से कंधा मिलाकर बिहार के विकास के लिए सतत प्रयत्नशील रहे और हम बिहार में एक ऐसी 'लोक-कल्याणकारी राज्य' की अवधारणा को स्थापित करने वाली सरकार लाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

श्री शाह ने कहा कि बिहार में विकास की अपार सम्भावनाएँ हैं चाहे वह पर्यटन का क्षेत्र हो, बिजली में सुधार की व्यापक जरूरत हो, औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने की बात हो या फिर शिक्षा और स्वास्थ्य की बात हो। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार को जवाब देना चाहिए कि राजद और जद (यू) के 25 वर्षो के शासन के बावजूद बिहार में विकास की दयनीय स्थिति क्यों है? उन्होंने कहा कि जब तक भाजपा बिहार में सरकार में साथ रही, बिहार का विकास काफी तेज गति से

होता रहा, लेकिन भाजपा के सरकार से निकलते ही विकास कार्यों पर रोक लग गयी, अपराध का ग्राफ बढ़ा है, विकास रुका है, जीडीपी में गिरावट आई है और कानून व्यवस्था चरमराई है। उन्होंने कहा कि श्री नीतीश कुमार ने बिहार के लोगों के जनादेश के साथ विश्वासघात किया है। उन्होंने कहा कि बिहार की जनता सब समझती है और वह इन लोगों के झांसे में अब और आने वाली नहीं है। उन्होंने कहा कि मुझे पूर्ण विश्वास है कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के कुशल नेतृत्व में बिहार के समग्र विकास के लिए राजग राज्य में दो-तिहाई बहुमत की सरकार बनायेगी।

राजद और जद (यू) के अलोकतांत्रिक गठबंधन पर करारा प्रहार करते हुए श्री शाह ने कहा कि यह केवल सत्ता प्राप्ति के उद्देश्य से किया गया एक पूर्णत: अनैतिक गठबंधन है। उन्होंने कहा कि यह श्री नीतीश कुमार थे जिन्होंने जनता को श्री लालू प्रसाद यादव के जंगलराज से मुक्ति का नारा दिया था। उन्होंने कहा कि इस स्थिति में जबकि उन्होंने भ्रष्टाचार और जंगलराज के प्रतीक श्री लालू यादव से हाथ मिला लिया, श्री नीतीश कुमार कैसे जनता को विकास का भरोसा दे सकते हैं?

आरक्षण के मुद्दे पर बोलते हुए श्री शाह ने कहा कि अपनी स्थापना और पूर्व में जनसंघ के समय से ही भारतीय जनता पार्टी दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों और अति पिछड़ों के आरक्षण के पक्ष में रही है। इन वर्गों के विकास के लिए भाजपा वर्तमान संवैधानिक आरक्षण व्यवस्था का पूर्णत: समर्थन करती है। भाजपा वर्तमान आरक्षण नीति के संवैधानिक पुनर्विचार के पक्ष में नहीं है।

उन्होंने बिहार की जनता से अपील करते हुए कहा कि आपने लालू जी को 15 वर्ष दिए, कांग्रेस को भी आपने एक लम्बा समय दिया, आपने नीतीश जी को भी देखा - अब भाजपा को भी एक मौका दीजिये और मैं आप सभी को विश्वास दिलाता हूँ कि केवल पाँच वर्षों में हम बिहार को देश के अग्रणी राज्यों की पंक्ति में लाकर खड़ा कर देंगे। ■

तमिलनाडु से आये देवेन्द्र समाज के प्रतिनिधिमंडल ने प्रधानमंत्री से की मुलाकात

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी से तमिलनाडु से आये देवेन्द्र कुलावेल्लार समाज के प्रतिनिधिमंडल ने 16 सितम्बर को सौजन्य मुलाकात की और प्रधानमंत्री का अभिवादन किया। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह एवं केंद्रीय राज्य मंत्री श्री पोनराधाकृष्णन भी उपस्थित रहे।

मदुरै के देवेन्द्रचौरिटेबल ट्रस्ट के चेयरमैन श्री थंगराज के नेतृत्व में आये हुए इस 101 मेंबर डेलीगेशन ने नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश की प्रगति की तेज गति की सराहना की और कहा कि पूरे विश्व में भारत की शान और गौरव बढ़ रहा है। श्री थंगराज ने देवेन्द्र समाज के इतिहास की भूमिका दी और सामाजिक समरसता की प्रतिबद्धता व्यक्त की और ज्ञापन सौंपा।

तमिलनाडु से आये देवेंद्र समाज के इस प्रतिनिधिमंडल का स्वागत करते हुए श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि देवेन्द्र समाज ने स्वार्थ नहीं, स्वाभिमान की दिशा अपनाई, यह अपने आप में असामान्य सामाजिक सुधार है। इस से आने वाली पीढ़ियों को आत्मनिर्भरता और गौरव का रास्ता मिलेगा। श्री नरेंद्र मोदी ने देवेन्द्र समाज के कुम्भाभिषेक समारोह में उपस्थित रहने के निमंत्रण को सैद्धांतिक रूप से स्वीकार किया और देवेन्द्र समाज के उच्चतर मूल्यों की प्रशंसा की और कहा कि केंद्र सरकार देवेन्द्रकुलावेल्लार नाम औपचारिक रूप से रखने के लिए कार्यवाही करेगी।

भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह ने प्रासंगिक उद्बोधन में देवेन्द्र समाज की सांस्कृतिक परंपरा का जिक्र किया और देश के विकास में उनके योगदान को सराहा।

भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री श्री मुरलीधर राव और श्री गुरुमूर्ति भी इस अवसर पर उपस्थित रहे। ■

प्रधानमंत्री को देश-विदेश से मिली जन्मदिन की बधाई

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 17 सितंबर को 65 बरस के हो गए। इस मौके पर देश-विदेश के नेताओं ने उन्हें जन्मदिवस की बधाई दी। विदेशी नेताओं में चीन के राष्ट्रपति श्री शी जिनफिंग, रुस के प्रधानमंत्री श्री दमित्री मेदवेदेव और जर्मनी की चांसलर श्रीमती अंजेला मार्केल आदि ने उन्हें

बधाई दी। मोदी ने ट्विटर के माध्यम से सबका धन्यवाद किया। रूसी राष्ट्रपति द्वारा भेजे गए एक बधाई संदेश में कहा गया कि हमारे दो देशों के बीच विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी वाले अत्यधिक विशेष संबंधों को मजबूत बनाने, क्षेत्रीय और वैश्विक एजेंडे के जरूरी मुद्दों के समाधान के लिए रूसी-भारतीय सहयोग की क्षमता बढ़ाने के लिए हम आपके प्रयासों की सराहना करते हैं।

वैसे श्री मोदी के लिए उनका जन्म दिन अन्य दिनों की तरह सामान्य रहा और वह बिना किसी औपचारिक समारोह के अपने आधिकारिक कार्यक्रमों में व्यस्त रहे। वह 'शौर्यांजलि' प्रदर्शनी में शामिल हुए जो 1965 के युद्ध में भारत की पाकिस्तान पर विजय की याद में दिल्ली स्थित राजपथ के लॉन में आयोजित की गयी थी। शुभकामना संदेश में राष्ट्रपति श्री प्रणव मुखर्जी ने कहा कि आपकी कड़ी मेहनत, उत्साह और अलग हट कर सोचने के अंदाज की देश और विदेश में बड़े पैमाने पर सराहना हुई है। प्रधानमंत्री ने ट्वीट के जरिए राष्ट्रपति की शुभकामना के जवाब में कहा कि आपकी शुभकामनाओं से मैं अत्यधिक अनुग्रहीत हुआ। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आपके विवेक और ज्ञान से सबको काफी कुछ सीखने को मिलता है।

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह ने माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट पर प्रधानमंत्री मोदी को बधाई देते हुए कहा कि वह ईश्वर से 'उनकी लंबी आयु और उनके अच्छे स्वास्थ्य' की कामना करते हैं।

केंद्रीय गृह मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने भी उन्हें बधाई देते हुए ट्विटर पर लिखा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को आज उनके जन्मदिन पर बधाई हो। ईश्वर उन्हें अच्छा स्वास्थ्य और दीर्घायु दे।

वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली ने ट्वीट किया कि मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को आज उनके जन्मदिन पर शुभकामनाएं देता हूं। ईश्वर उन्हें अच्छा स्वास्थ्य और उनके सभी प्रयासों में उन्हें सफलता प्रदान करे। ■

'शौर्यांजलि' देखने पहुंचे प्रधानमंत्री

1965 की जंग में सैनिकों के बहादुरी भरे कारनामों पर गर्व : मोदी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 17 सितंबर को 1965 के युद्ध की स्वर्ण जयंती के अवसर पर राजपथ लॉन्स, नई दिल्ली में आयोजित स्मृति प्रदर्शनी 'शौर्यांजलि' देखने पहुंचे। इस प्रदर्शनी में देश की सीमाओं की रक्षा करने वाले भारतीय सशस्त्र सेनाओं के कर्मियों की अदम्य वीरता, साहस और बलिदान को दर्शाया गया था।

प्रधानमंत्री ने प्रदर्शनी तथा विभिन्न क्षेत्रों में हुई लड़ाइयों के युद्ध दृश्यों के पुन: सृजनों को देखा। उन्होंने 1965 के युद्ध के कुछ पुराने योद्धाओं से भी मुलाकात की। इस अवसर पर सेना, नौसेना और वायु सेना प्रमुख और कई वरिष्ठ केंद्रीय मंत्री भी उपस्थित थे। प्रधानमंत्री ने बाद में ट्वीट कर अपने संदेश में कहा कि 1965 के युद्ध के दौरान हमारे सशस्त्र बलों की वीरता, साहस और बलिदान को प्रत्येक भारतीय सदैव याद रखेगा। हमें उन पर गर्व है। ■

प्यू (पीईडब्ल्यू) सर्वेक्षण

प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता रेटिंग 87 प्रतिशत पहुंची

अपने जन्मदिन पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को शुभकानाओं के साथ-साथ भारत की जनता से एक बड़ा संदेश भी मिला। संदेश यह था कि जनता की नजरों में उनका कद और बढ़ गया है। एक ताजा सर्वे के मुताबिक पिछले साल सरकार बनाने के बाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता में इजाफा हुआ है। अमेरिकी शोध केंद्र प्यू (पीईडब्ल्यू) द्वारा जारी सर्वेक्षण के अनुसार श्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता रेटिंग 87 फीसदी पहुंच गई है।

अमेरिकी शोध केंद्र प्यू (पीईडब्ल्यू) के 17 सितंबर को जारी सर्वेक्षण के अनुसार पिछले साल भारत में भाजपा नीत सरकार के सत्ता में आने के बाद प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता रेटिंग में तेजी से इजाफा हुआ है। प्यू ने छह अप्रैल से 19 मई, 2015 तक भारत में 2452 लोगों के बीच कराये गये अपने सर्वेक्षण के परिणामों में कहा कि श्री मोदी ने अपनी नीतियों और शासन से न केवल देश में भारतीयों का गौरव बढ़ाया है, बल्कि उनकी लोकप्रियता की रेटिंग उछलकर 87 प्रतिशत हो गयी है और परंपरागत कांग्रेसी आधार वाले स्थानों से भी उन्हें समर्थन मिल रहा है।

प्यू ने एक बयान में कहा कि हालांकि श्री मोदी ने भारत की परंपरागत दलीय राजनीति को आगे बढ़ाया है। प्रधानमंत्री और उनकी पार्टी को देश के सामने मौजूद अधिकतर चुनौतियों पर भाजपा के समर्थकों के साथ साथ विपक्षी कांग्रेसी के समर्थकों से भी समर्थन मिल रहा है। सर्वेक्षण के अनुसार श्री मोदी और भाजपा को ग्रामीण इलाकों में और कांग्रेस के परंपरागत मजबूत गढ़ों में बड़ा समर्थन मिल रहा है। बड़ी संख्या में कांग्रेस समर्थकों ने आतंकवाद तथा भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रधानमंत्री के प्रयासों को सही माना है। इनकी संख्या 56-56 प्रतिशत रही। खुद को कांग्रेस का समर्थक बताने वाले 10 में से करीब छह लोगों ने शौचालयों, बेरोजगारी, गरीबों की मदद और महंगाई से निपटने के मोदी के तरीके को मंजूर किया है। सर्वेक्षण के मुताबिक श्री मोदी शहरी और ग्रामीण दोनों ही इलाकों में कांग्रेस के नेता माने जाने वाले श्री राहुल गांधी से अधिक लोकप्रिय हैं। ■

स्वच्छ भारत और नमामि गंगे परियोजना

सरकार नमामि गंगे परियोजना को सफल बनाने के लिए प्रतिबद्ध : अरुण जेटली

वित्तमंत्री श्री अरुण जेटली ने कहा है कि केंद्र आगामी 3 से 4 वर्षो में स्वच्छ भारत अभियान के समान नमामि गंगे परियोजना को बड़ी सफलता दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है। श्री जेटली 11 सितंबर को केरल में कोल्लम जिले के अमृतपुरी में आध्यात्मिक गुरू माता अमृतानंदमयी से प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के स्वच्छ भारत और नमामि गंगे परियोजना के तहत गंगा नदी के किनारे निर्धन गांवों में शौचालय निर्माण के लिए 100 करोड़ रूपए का चेक प्राप्त करने के अवसर पर संबोधित कर रहे थे।

उन्होंने कहा कि चालीस प्रतिशत भारतीय गंगा नदी पर निर्भर हैं और पवित्र नदी को साफ करने के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए जा चुके हैं। स्वच्छ भारत अभियान के पहले चरण के अंतर्गत सभी स्कूलों में शौचालय के निर्माण के लक्ष्य को बेहद सफलता मिली है और सभी घरों मे शौचालय प्रदान करने के प्रयास किए जा रहे हैं। इस अभियान में समाज के सभी क्षेत्रों से लोगों और अनिवासी भारतीयों के शामिल होने से यह अभियान सरकारी अभियान से बढ़कर एक जन अभियान बन चुका है। 100 करोड़ रुपये का यह दान अन्य लोगों को एक सांकेतिक संदेश देगा। अगले पांच वर्षो में 20,000 करोड़ रुपये के आवंटन के साथ नमामि गंगे परियोजना को सरकार ने इस वर्ष मई में अनुमति प्रदान की। इस अवसर पर बोलते हुए माता अमृतानंदमयी ने कहा कि गरीबों की दयालुतापूर्वक सेवा करना ही असली पूजा है। इस परियोजना से लोगों को आवश्यक सुविधाएं प्रदान की जा सकेगी। इसके साथ ही केरल में शौचालयों के निर्माण के लिए 100 करोड़ रूपये की लागत से एक अन्य परियोजना की जल्दी ही शुरुआत की जाएगी।

इस अवसर पर पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री ओ.राजागोपाल और सांसद श्री के.सी वेणुगोपाल और अन्य विशिष्ट अतिथि उपस्थित थे। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और माता अमृतानंदमयी ने नमामि गंगा परियोजना में माता अमृतानंदमयी की भागीदारी के संबंध में उनकी 28 मार्च, 2015 को दिल्ली यात्रा के दौरान चर्चा की थी। प्रधानमंत्री ने मठ द्वारा स्वच्छ भारत अभियान के अनुरूप पर्यावरण संबंधी कार्यक्रम में भागीदारी के लिए उनका धन्यवाद दिया था। ■